सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
YouTube

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 286, नई दिल्ली । बुधवार, 25 दिसम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अच्छे और सच्चे रिश्ते न तो खरीदे जा सकते हैं, न ही उधार लिए जा सकते हैं, इसलिए उन लोगों को जरूर महत्व दें, जो आपको महत्व देते हैं।

03 जिला कांग्रेस कमेटियों ने बाबा साहेब आंबेडकर सम्मान मार्च....
06 अटल जी सकारात्मक ऊर्जा के प्रेरणास्रोत थें।
08 बच्चों के समग्र विकास में योगदान दें- स्वामी रामदयाल महाराज

दिल्ली-एनसीआर से हटी ग्रैप-4 की पाबंदियां जानें क्या खुला रहेगा और क्या बंद

संजय बाटला

दिल्ली वालों के लिए एक राहत की खबर है। दिल्ली-एनसीआर में कई दिनों से हवा की गुणवत्ता सही है। इसको देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेप चार के प्रतिबंधों को हटा दिया है। हालांकि प्रदूषण स्तर को प्रबंधित करने के लिए चरण- 1 2 और 3 के तहत उपाय लागू रहेंगे। खबर के माध्यम से पढ़िए किन चीजों पर छूट मिलेगी।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता निगरानी पैनल ने मंगलवार को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तहत चरण IV ('गंभीर+') उपायों को रद्द कर दिया।

हालांकि, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 24 दिसंबर को घोषणा की कि वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए चरण I, II और III के तहत कार्रवाई लागू रहेगी।

401 ('गंभीर') के उच्चतम स्तर से कम AQI

यह निर्णय 24 दिसंबर को शाम 4 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बढ़कर 369 ('बहुत खराब') हो जाने के बाद आया है, जो 16 दिसंबर को रिकॉर्ड किए गए 401 ('गंभीर') के उच्चतम स्तर से कम है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) के पूर्वानुमानों के अनुसार, हवा की गुणवत्ता में सुधार का श्रेय अनुकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों को दिया गया, जिसमें हवा की गति में सुधार भी शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप, चरण IV के उपाय शुरू में तब लागू किए गए थे जब 16 दिसंबर को AQI का स्तर 400 के स्तर को पार कर गया था। इन उपायों का उद्देश्य गंभीर प्रदूषण स्तर पर अंकुश लगाना था और इसमें औद्योगिक गतिविधियों, निर्माण और दिल्ली में गैर-आवश्यक ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध शामिल था।

ग्रेप चार के प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। इसलिए दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध हट गया है। अब बीएस चार डीजल वाले ट्रैक भी दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे।

GRAP- I, II और III के चरण अभी रहेंगे लागू

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) की गंभीरता के आधार पर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली-एनसीआर (Delhi NCR) में लागू आपातकालीन उपायों का एक सेट है।

केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल ने निरंतर सतर्कता के महत्व पर जोर दिया। आयोग ने कहा, "संशोधित जीआरएपी के चरण I, II और III के तहत कार्रवाई लागू रहेगी और पूरे एनसीआर में संबंधित सभी एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित, निगरानी और समीक्षा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि AQI का स्तर आगे न गिरे।

GRAP-III के तहत नागरिक चार्टर का सख्ती से करें पालन

नागरिकों से स्टेज III के तहत दिशानिर्देशों का पालन करने का भी आग्रह किया गया। आयोग ने कहा, "सर्दियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए, जब मौसम की स्थिति हमेशा अनुकूल नहीं हो सकती है, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि AQI का स्तर आगे न गिरे, नागरिकों से अनुरोध है कि वे GRAP-III के तहत नागरिक चार्टर का सख्ती से पालन करें।"

जीआरएपी पर सीएक्यूएम उप-समिति ने आश्वासन दिया कि वह वायु गुणवत्ता की निगरानी करना जारी रखेगी और आवश्यकतानुसार उचित निर्देश जारी करेगी, उन्होंने कहा कि "उप-समिति वायु गुणवत्ता परिदृश्य पर कड़ी नजर रखेगी और समय-समय पर स्थिति की समीक्षा करेगी।₹ दिल्ली में वायु गुणवत्ता और आईएमडी/आईआईटीएम द्वारा किए गए पूर्वानुमानों के आधार पर आगे उचित निर्णय लिए जाएंगे।"

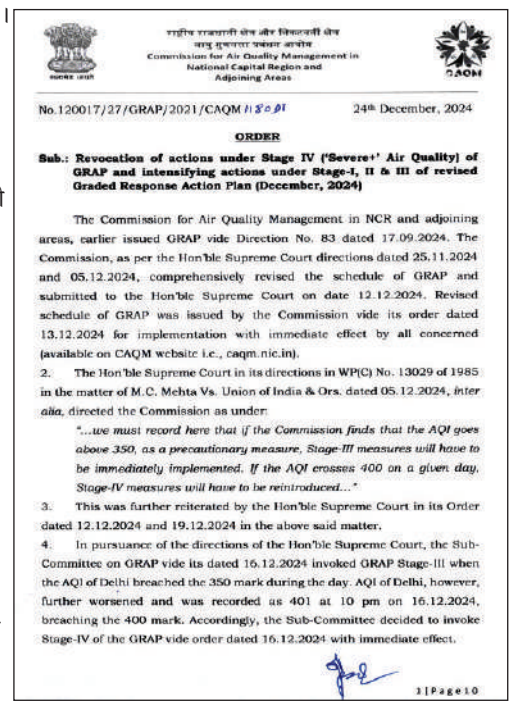

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्र वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas
CAQM

No.120017/27/GRAP/2021/CAQM/18081 — 24th December, 2024

ORDER

Sub.: Revocation of actions under Stage IV ('Severe+' Air Quality) of GRAP and intensifying actions under Stage-I, II & III of revised Graded Response Action Plan (December, 2024)

The Commission for Air Quality Management in NCR and adjoining areas, earlier issued GRAP vide Direction No. 83 dated 17.09.2024. The Commission, as per the Hon'ble Supreme Court directions dated 25.11.2024 and 05.12.2024, comprehensively revised the schedule of GRAP and submitted to the Hon'ble Supreme Court on date 12.12.2024. Revised schedule of GRAP was issued by the Commission vide its order dated 13.12.2024 for implementation with immediate effect by all concerned (available on CAQM website i.e., caqm.nic.in).

2. The Hon'ble Supreme Court in its directions in WP(C) No. 13029 of 1985 in the matter of M.C. Mehta Vs. Union of India & Ors. dated 05.12.2024, *inter alia*, directed the Commission as under:

"...we must record here that if the Commission finds that the AQI goes above 350, as a precautionary measure, Stage-III measures will have to be immediately implemented. If the AQI crosses 400 on a given day, Stage-IV measures will have to be reintroduced..."

3. This was further reiterated by the Hon'ble Supreme Court in its Order dated 12.12.2024 and 19.12.2024 in the above said matter.

4. In pursuance of the directions of the Hon'ble Supreme Court, the Sub-Committee on GRAP vide its dated 16.12.2024 invoked GRAP Stage-III when the AQI of Delhi breached the 350 mark during the day. AQI of Delhi, however, further worsened and was recorded as 401 at 10 pm on 16.12.2024, breaching the 400 mark. Accordingly, the Sub-Committee decided to invoke Stage-IV of the GRAP vide order dated 16.12.2024 with immediate effect.

1 | Page 10

दिल्ली में बारिश के बाद बढ़ी ठंड, कई जगहों पर लंबा जाम

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार शाम को ठंडी हवाओं के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई जिससे तापमान में गिरावट आई और ठंड बढ़ गई। नोएडा गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने आगे भी बूंदाबांदी की संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते दिल्ली एनसीआर में मौसम बदला है। जिस कारण बारिश वाला मौसम बना है और ठंड भी बढ़ी हुई है।

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार शाम को ठंडी हवा के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई। इससे राजधानी और आसपास क शहरों में सर्दी बढ़ गई। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में भी हल्की बारिश बारिश हुई है। वहीं, बारिश के कारण दिल्ली के रिंग रोड पर जगह-जगह लंबा जाम भी लगा। आज सुबह से बादलों की आवाजाही बनी हुई थी और बूंदाबांदी की संभावना जताई जा रही थी।

दिल्ली में बारिश के कारण कई जगहों पर जाम लगा हुआ है। इस कारण लोगों को परेशानी हो रही है। ऑफिस के बाद घर के लिए निकले लोग जाम में फंस गए। जाम से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई।

दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से बूंदाबांदी का मौसम बना हुआ है। सोमवार को भी दिन में बूंदाबांदी हुई थी। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते ऐसा मौसम बना हुआ है। उधर, पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है।

दिल्ली में कितना दर्ज हुआ तापमान

दिल्ली में मंगलवार को अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। यह औसत से 2.4 डिग्री कम तापमान था।

सप्ताहभर ऐसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, सप्ताहभर बारिश और कोहरे का मौसम रहने वाला है। बुधवार को घने कोहरे की संभावना है। उसके अगले दिन यानी बृहस्पतिवार को बादल और हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। अगले दिन भी बूंदाबांदी की संभावना है।

परिवहन निगम ने दिया नए साल का तोहफा, घटाया गया जनरथ बसों का किराया, इतने प्रतिशत की हुई कमी

नए साल पर यूपी के परिवहन निगम ने यात्रियों को तोहफा दिया है। वातानुकूलित जनरथ सेवाओं के किराये में 20 फीसदी की कमी की गई है।

लखनऊ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मशती पर परिवहन निगम ने यात्रियों को तोहफा दिया है। वातानुकूलित जनरथ सेवाओं में 20 फीसदी की कमी कर दी गई है। यह जानकारी देते हुए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि वातानुकूलित जनरथ बस का किराया 25 दिसंबर से 1.63 रुपये प्रति किलोमीटर की जगह 1.45 रूपये प्रति यात्री प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। इसके अलावा 2बाई 2 जनरथ बस सेवा का किराया 1.93 रूपये प्रति किलोमीटर से घटाकर 1.60 रूपये यात्री प्रति किलोमीटर कर दिया गया है।

मेला क्षेत्र में लगेगी परिवहन प्रदर्शनी

परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि महाकुम्भ-2025 में परिवहन विभाग की मेला क्षेत्र में प्रदर्शनी/स्टॉल लगाए जाएंगे। इस संबंध में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया है। महाकुम्भ में आने वाले श्रद्धालुओं को विभाग की ओर से पाकेट कैलेंडर वितरित कराने, सड़क सुरक्षा से संबंधित आडियो एवं वीडियो सार्टफिल्म बनाकर प्रदर्शित कराने एवं आडियो जिंगल सुनाये जाने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्य मार्गों का चिन्हीकरण करते हुए सड़क सुरक्षा कोष से एलईडी स्क्रीनयुक्त पब्लिसिटी वैन के माध्यम से सड़क सुरक्षा नियमों/यातायात नियमों का प्रचार प्रसार किया जाएगा।

गौतमबुद्ध नगर में सड़क सुरक्षा पर कड़े कदम अवैध कट होंगे बंद, 29 ब्लैक स्पॉट्स में सुधार

इशिका मुख्य रिपोर्टर

ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित कलेक्ट्रेट में सोमवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) मंगलेश दुबे ने जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त की।

अवैध कट्स पर सख्ती

बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले में मौजूद सभी अवैध कट्स को शीघ्र बंद किया जाएगा, क्योंकि ये सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण बनते जा रहे हैं।

ब्लैक स्पॉट्स की संख्या में वृद्धि

वर्ष 2023 में जिले में ब्लैक स्पॉट्स की संख्या 11 से बढ़कर 29 हो गई है, जो गंभीर चिंता का विषय है। इन स्थानों पर दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए, सुधार कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं।

यातायात नियमों के प्रति जागरूकता

अपर जिलाधिकारी ने सभी वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया, ताकि सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मृत्यु दर में कमी लाई जा सके।

अवैध स्टैंड और अतिक्रमण पर कार्रवाई

परिवहन विभाग, यातायात पुलिस और तीनों प्राधिकरणों को निर्देश दिया गया है कि वे जिले में अवैध बस, टेंपो और टैक्सी स्टैंड्स की पहचान कर उन पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें, जिससे अतिक्रमण पर अंकुश लगाया जा सके।

हिट एंड रन मामलों में सहायता

अपर जिलाधिकारी ने एआरटीओ को निर्देशित किया कि हिट एंड रन मामलों में पीड़ितों को सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए गठित समिति के माध्यम से सभी प्रकरणों पर विचार कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

ओवरलोड वाहनों पर निगरानी

सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ओवरलोड वाहनों और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

इन सभी प्रयासों का उद्देश्य जिले में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या और उनसे होने वाली मृत्यु दर को कम करना है, ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

"हमारा काम नहीं' तो "हमारा वोट नहीं" ट्रांसपोटर्स ने बैठक कर लिया फैसला

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने एक मीटिंग अपनी लंबित मांगो को लगातार दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार द्वारा अनसुना करने के खिलाफ गांधी पीस फाउंडेशन आ टी ओ में करी.

ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के मेंबर्स ने आज फैसला लिया की

"हमारा काम नहीं' तो "हमारा वोट नहीं" आज मीटिंग में ऑटो टैक्सी और बस वाले लोग थे.

ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने कहा की हमारी ज्यादातर मांगे और समस्याये दिल्ली सरकार द्वारा दी गई है. क्योंकि ट्रांसपोर्ट विभाग और MCD दिल्ली सरकार के अधीन है बल्कि दिल्ली में MCD और दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की है.

कुछ मुद्दे केंद्र सरकार से भी जुड़े है. जो काफी सालो से लंबित है.

ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने अपनी लंबित मांगो का ज्ञापन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्दर मोदी जी और दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती आतिशी सिंह जी को सौपा.

संजय सम्राट का कहना है की अगर केंद्र और दिल्ली सरकार ने हमारी मांगो पर गौर नहीं किया तो दिल्ली के ऑटो टैक्सी बस वाले दिल्ली विधान सभा के चुनाव का बहिष्कार करेंगे.

ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट का कहना है की सरकार और उनकी संस्थाएं ऑटो -टैक्सी- बसों वालो पर लगातार अत्याचार कर रहीं है. इनकी दमनकारी भृष्ट नीतियों ने ऑटो - टैक्सी- बस वालो का आर्थिक और मानसिक शोषण लगातार हों रहा है.हमारी ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन भी लगातार इनकी दमनकारी नीतियों का लगातार धरने प्रदर्शन करके विरोध करती रही हैं.

हमारी पुरानी लंबित मांगे :-

1:- आल इंडिया टूरिस्ट परमिट की डीजल टैक्सी -LMV BS 4 को किसी भी ग्रेप मे बंद ना किया जाए, क्योंकी इन गाड़ियों से हमारी रोजी रोटी चलती है

2:- झूली झूली फिटनेस सेंटर पर फिटनेस की अपॉइंटमेंट बहुत देर से मिल रही हैं.

ज्यादातर कमर्सयल गाड़ियों को झुल झुली भेज दिया गया हैं. इन सारी गाड़ियों को वापिस बुराड़ी फिटनेस सेंटर भेजा जाए.

3:- पेनिक बटन के नाम पर हजारों रुपए दोबारा लिए जा रहे हैं बल्कि पेनिक बटन की वजह से दिल्ली मे इन्नोवा गाड़ियाँ भी रजिस्टर्ड नहीं हो रही हैं. इसको अब व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के नाम से ये पुरानी गाड़ियों मे लगा रहें है. इस पेनिक बटन के नाम से करोडो रुपये का भ्ष्टाचार हों चूका है. इसको तुरन्त हटाया जाना चाहिए.

4:- AITP टैक्सी बसों में स्पीड लिमिट डिवाइस (स्पीड गवर्नर)लगाया हुआ हैं. इसको तुरन्त हटाया जाए

5:- CNG के दाम कम किये जाए.

6:- डीजल पेट्रोल को GST के दायरे में लाया जाए.

7:- MCD टोल टैक्सी दिल्ली में पंजीकृत कमर्सयल गाड़ियों से हटाया जाए.

8:- नाजायज रेपिड़ो बाइक टैक्सी को बंद किया जाए.

9:- दिल्ली सरकार ऑटो टैक्सीयों के लिए अपना ऐप बनाये.

10:- सारे ड्राइवर्स की जान -माल सुरक्षा की गारंटी और उनका जीवन और हेल्थ इन्शुरन्स भी सरकार की तरफ से हों.

आज की मीटिंग में आल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट यूनियन शामिल रही और उनके उपाध्यक्ष श्री रवि राठौर ने रैपिड बाइक टैक्सी जो की नाजयाज चल रही है और दिल्ली में प्रतिबंध है इनके ऐप को बंद किये जाने की मांग की.

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमैंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

क्रिसमस पर जन्नत से कम नहीं लगते दिल्ली के 5 चर्च, दिखाई देती है अनोखी धूम

क्रिसमस की तैयारियां कई दिनों पहले से ही शुरू हो जाती है। दिल्ली भी क्रिसमस मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कई मॉल्स और कैफे इसके लिए सज चुके हैं लेकिन यहां के चर्च की बात ही कुछ और होती है क्रिसमस मासेस से लेकर खूबसूरत सजावट सजावट तक दिल्ली के 5 चर्च में क्रिसमस के मौके पर अनोखा अनुभव मिलती है।

नई दिल्ली। क्रिसमस का त्योहार आ चुका है और दिल्ली में इसकी धूम चारों ओर देखने को मिल सकती है। कैफेज से लेकर शॉपिंग मॉल्स तक क्रिसमस के रंग में रंगे हुए हैं। क्रिसमस की सजावट, क्रिसमस कैरोल, तरह-तरह की डिशेज और लोगों के चेहरे की खुशी इस त्योहार को बेहद खास बनाती है। इस मौके पर हम लोग पार्टी करते हैं, घूमने जाते हैं और बाहर छाए क्रिसमस के आनंद का लुत्फ उठाते हैं, लेकिन ऐसे में चर्च जाकर क्रिसमस सेलिब्रेट करना न भूलें। इसलिए हम यहां दिल्ली के 5 मशहूर चर्च (Christmas Church decorations 2024) के बारे में आपको बताने वाले हैं। क्रिसमस के मौके पर यहां खास आयोजन होता है और दूर-दूर से लोग यहां क्रिसमस का आयोजन देखने आते हैं। आइए जानें क्रिसमस के लिए दिल्ली के कुछ चर्च।

सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल

दिल्ली के सबसे बड़े और सबसे फेमस चर्चों में से एक है- सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल। यह चर्च अपनी गोथिक आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। क्रिसमस के मौके पर यह चर्च रंग-बिरंगे रोशनी से जगमगा उठता है। यहां दिल्ली और इसके आस-पास रहने वाले कई लोग क्रिसमस मनाने आते हैं। इसलिए यहां सही समय से पहुंचना जरूरी है। नहीं तो आपको लंबी लाइन में घंटों खड़े रहना पड़ सकता है। इसका सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पटेल चौक है।

सेंट जेम्स चर्च भी दिल्ली के सबसे पुराने चर्च में से एक है। यह दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास है और इसका खास ऐतिहासिक महत्व भी है। यह चर्च अपनी शांत और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए

भी जाना जाता है। क्रिसमस के मौके पर यहां विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाती हैं। इस चर्च का सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कश्मीरी गेट है।

सेंट मैरी कैथोलिक चर्च

यह चर्च भी बेहद पुराना है और दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित है। अपनी ऐतिहासिक इमारत के लिए जाना जाने वाला यह चर्च क्रिसमस पर जाने के लिए बेस्ट है। चर्च की दीवारों पर क्राइस्ट और मैरी के जीवन से जुड़ी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। यहां जाने के लिए सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन लाल किला और चांदनी चौक हैं।

सेंटेनरी मेथोडिस्ट चर्च

यह चर्च अपनी आधुनिक वास्तुकला के लिए जाना जाता है। क्रिसमस के मौके पर यहां कैरोलिंग और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह लोधी रोड पर स्थित है और यहां जाने के लिए जवाहर लाल नेहरू मेट्रो स्टेशन पर उतरें।

कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन

यह चर्च अपनी भव्य इमारत के लिए जाना जाता है। क्रिसमस के मौके पर यहां मिडनाइट मास आयोजित किया जाता है। यह चर्च स्पिरिचुएलिटी और आर्ट के लिए जाना जाता है। यहां जाने के लिए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है।

इन चर्चों के अलावा दिल्ली में कई अन्य चर्च भी हैं जो क्रिसमस के मौके पर खूबसूरती से सजाये जाते हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी चर्च चुन सकते हैं। दिल्ली के इन चर्चों में जाकर आप क्रिसमस का त्योहार एक अलग ही अंदाज में मना सकते हैं। यहां आपको शांति और आनंद का अनुभव होगा।

क्रिसमस के मौके पर दिल्ली घूमने का प्लान बनाते समय इन बातों का ध्यान रखें-

ट्रैफिक- क्रिसमस के मौके पर दिल्ली में ट्रैफिक काफी ज्यादा रहता है। इसलिए आप पहले से ही इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए घर से बाहर निकलें।

होटल- अगर आप दिल्ली में रुकने का प्लान बना रहे हैं तो पहले से ही होटल बुक कर लें।

खाना- दिल्ली में आपको कई तरह के रेस्तरां मिल जाएंगे जहां आप क्रिसमस की खास मील का मजा ले सकते हैं।

30 दिनों तक रोजाना खाएं एक मुट्ठी अंकुरित मेथी, सेहत में नजर आएंगे कई चौंकाने वाले बदलाव

अंकुरित मेथी एक सुपरफूड है जिसे डाइट का हिस्सा बनाने पर सेहत को कई फायदे मिल सकते हैं। 30 दिनों तक रोजाना एक मुट्ठी अंकुरित मेथी खाने से आप अपनी सेहत में कई चौंकाने वाले बदलाव देख सकते हैं। आइए इस आर्टिकल में आपको विस्तार से बताते हैं कि यह किस तरह से आपकी सेहत के लिए गुणकारी है।

नई दिल्ली। अंकुरित मेथी विटामिन, न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है। इसमें विटामिन C, A और B कॉम्प्लेक्स जैसे कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसके अलावा, प्रोटीन, कैल्शियम और फाइबर भी इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन-सी आपकी इम्युनिटी को बढ़ाता है, जबकि विटामिन-ए आंखों के लिए अच्छा होता है। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन आपके शरीर की एनर्जी को बढ़ाते हैं। प्रोटीन मसल्स की ग्रोथ में मदद करता है, वहीं कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है और फाइबर डाइजेशन को बेहतर बनाता है। आइए यहां आपको बताते हैं कि रोजाना 30 दिनों तक खाली पेट अंकुरित मेथी खाने से सेहत को क्या-कुछ फायदे मिल सकते हैं।

30 दिनों तक अंकुरित मेथी खाने के फायदे

बेहतर डाइजेशन

अंकुरित मेथी में मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है, ऐसे में अगर आप रोजाना 30 दिनों तक इसे डाइट में शामिल करते हैं तो इससे कब्ज, एसिडिटी और गैस जैसी समस्याओं से राहत मिल सकती है।

इम्युनिटी बढ़ाए

अंकुरित मेथी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं, इसलिए रोजाना एक महीने तक इसे खाने पर आप कई बीमारियों से बचे रह सकते हैं।

कंट्रोल में रहेगा शुगर लेवल

अंकुरित मेथी में मौजूद कुछ एंजाइम ब्लड शुगर के स्तर को काबू में करने में मदद करते हैं, जिससे डायबिटीज के मरीजों को फायदा मिलता है। इसलिए आप भी 30 दिनों तक खाली पेट इसे खाने से अपने शुगर लेवल को मेंटेन रख सकते हैं।

हार्ट के लिए फायदेमंद

अंकुरित मेथी में मौजूद पोषक तत्व हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, इसलिए एक महीने के लिए इन्हें डेली डाइट का हिस्सा बनाने पर आप पाएंगे कि हार्ट डिजीज का खतरा काफी कम हो गया है।

वेट लॉस में मददगार

अंकुरित मेथी में फाइबर की मात्रा भी भरपूर होती है, जो आपको लंबे समय तक फुल महसूस कराती है, ऐसे में डाइट में इसे शामिल करने पर पाएंगे कि ओवरईटिंग भी कम हो गई है और वजन घटाने में भी मदद मिल रही है।

हेल्दी स्किन और हेयर

अंकुरित मेथी में मौजूद विटामिन और न्यूट्रिएंट्स स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा, यह बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देती है और इन्हें मजबूत भी बनाती है।

कैसे खाएं अंकुरित मेथी?

अंकुरित मेथी को आप अपनी डाइट में कई तरीकों से शामिल कर सकते हैं।

सलाद में डालकर
सब्जी में डालकर
दही में मिलाकर
स्मूदी में मिलाकर
सूप में डालकर

कौन नहीं खा सकता अंकुरित मेथी?

अंकुरित मेथी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन कुछ लोगों को इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, जैसे कि गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं और जिन लोगों को एलर्जी की समस्या है।

खराब जीवनशैली और क्रोनिक बीमारियां

आज की भागम-भाग भरी जिंदगी में लाइफस्टाइल में हो रहा निरंतर बदलाव, भोजन की आदतों में परिवर्तन और विभिन्न पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव के चलते आज मनुष्य पर विभिन्न क्रोनिक बीमारियों/गैर-संचारी रोग यथा हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह, स्ट्रोक और गठिया, लंग्स कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, डिप्रेशन, अस्थमा और मोटापा(ओबैसिटी) आदि का खतरा मंडरा रहा है। आज क्रोनिक रोग/गैर-संचारी रोग वर्तमान में लगभग सभी देशों में वयस्कों में मृत्यु का प्रमुख कारण हैं और आने वाले वर्षों में मृत्यु दर में वृद्धि होने का अनुमान है। एक अनुमान के अनुसार वैश्विक स्तर पर, लगभग तीन में से एक वयस्क कई क्रॉनिक बीमारियों से पीड़ित है। सच तो यह है कि आज तंबाकू के बढ़ते उपयोग, शारीरिक गतिविधियों की कमी, कंप्यूटर-लैपटॉप और एंड्रॉयड मोबाइल का लगातार घंटों-घंटों तक अनवरत प्रयोग, तनाव और अवसाद भरा जीवन और खराब(जंक फूड और फास्ट फूड) और असमय खान-पान की आदतें, अत्यधिक शराब का उपयोग विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे रहा है। पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि हाल के कई अध्ययनों में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने हृदय रोगों के बढ़ते खतरे को लेकर सभी को अधिक सावधान किया है, क्यों कि आज हृदय रोगों और इसके कारण होने वाली जटिलताओं के कारण हर 33 सेकेंड में एक व्यक्ति की मौत हो रही है। सच तो यह है कि आज युवा आबादी गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों का सामना कर रही है। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2024 में सीएडी यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ युवाओं में विशेषकर मृत्यु का प्रमुख कारण रही है। आंकड़े बताते हैं कि इस साल 23 दिसंबर तक अकेले कोरोनरी आर्टरी डिजीज (सीएडी) के कारण 98.75 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई। यह बहुत ही गंभीर और संवेदनशील है कि आज हृदय संबंधित समस्याओं जैसे हार्ट अटैक-कार्डियक अरेस्ट से मरने वाले लोगों में बड़ी संख्या 40 से कम आयु के वयस्कों की है। अतः अंत में कहना ग़लत नहीं होगा कि हम अपनी जीवनशैली को अच्छा व बेहतर बनाकर क्रोनिक बीमारियों से स्वयं का बचाव कर सकते हैं। मसलन आज जरूरत इस बात की है कि हम धुम्रपान न करें और शराब न पिएं। प्रत्येक दिन हम शारीरिक रूप से स्वयं को सक्रिय रखें। हमेशा समय पर पौष्टिक और संतुलित भोजन करें। तनाव और अवसाद से दूर रहें, सकारात्मक रहें। मोटापा न होने दें, मतलब यह कि हम अपने वजन को नियंत्रित रखें। ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें। स्वयं को हमेशा हाइड्रेट रखें और नियमित रूप से स्वयं की स्वास्थ्य जांच या परीक्षण करवाएं।

सुनील कुमार महला

हरियाली और पर्यावरण (ट्री कवर द्विवार्षिक रिपोर्ट)

हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) द्वारा 21 दिसंबर 2024 को वन क्षेत्र और वृक्षावरण (ट्री कवर) पर रिपोर्ट(द्विवार्षिक रिपोर्ट) जारी की गई है।स्टेट ऑफ फारेस्ट रिपोर्ट (एसओएफआर) 2023 में यह कहा गया है कि पिछले तीन वर्षों के भीतर देश के वनों और वृक्षों के आवरण(ऐसे क्षेत्रों से है जहां वृक्ष दर्ज वन क्षेत्रों के बाहर मौजूद होते हैं) में 1,445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, जो पर्यावरण के लिहाज से बहुत ही अच्छी खबर है। अच्छी खबर इसलिए क्यों कि आज संपूर्ण विश्व समेत भारत भी ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि जैसी अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है।रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में वन क्षेत्र और वृक्षावरण (ट्री कवर) उसके कुल क्षेत्रफल का 25.17 फीसदी है, जो पिछले अनुमान से 156.41 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि को दर्शाता है। गौरतलब है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का कुल वन क्षेत्र 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर रिकॉर्ड किया गया, जो कुल क्षेत्र का 21.76 फीसदी है। वहीं वृक्षावरण यानी ट्री कवर को देखें तो यह 1,12,014.34 वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया, जो कुल क्षेत्र का करीब 3.41 फीसदी है।

हालांकि, यह बात अलग है कि रिपोर्ट के अनुसार देश भर में वन क्षेत्र में उल्लेखनीय गिरावट आई है। रिपोर्ट के अनुसार देश के असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, तेलंगाना और लद्दाख में वन क्षेत्रों में गिरावट देखी गई है। स्टेट ऑफ फारेस्ट रिपोर्ट (एसओएफआर) 2023 से पता चलता है कि पश्चिमी घाट से 2013 से 58.22 वर्ग किलोमीटर में फैले जंगल गायब हो चुके हैं।गौरतलब है कि पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल होने के साथ-साथ दुनिया में जैव विविधता का एक प्रमुख हॉटस्पॉट भी है। कहना ग़लत नहीं होगा कि पश्चिमी घाट से जंगलों का गायब होना पर्यावरण के लिहाज से बहुत ही चिंताजनक है।बहरहाल, यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वन क्षेत्रों में बदलाव वनों के विनाश और वनों के विस्तार दोनों ही तरह की गतिविधियों से होता है। कहना ग़लत नहीं होगा कि आज वन विनाश के लिए कहीं न कहीं देश में बढ़ती आबादी जिम्मेवार है ,जिसकी लगातार बढ़ती जरूरतों के लिए, विकास के बहाने से आज तेजी से जंगल काटे जा रहे हैं। बहरहाल, रिपोर्ट ने इस बात की भी पुष्टि की है कि इस दौरान जहां बेहद सघन वनों में 3,465.12 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। वहीं दूसरी तरफ मध्यम सघन वनों में 1,043.23 वर्ग किलोमीटर और 'खुले' वन में भी 2,480.11 वर्ग किलोमीटर की गिरावट आई है।

गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि एफ ए ओ ने अपनी नई रिपोर्ट "द स्टेट ऑफ वर्ल्डस फॉरेस्ट्स 2024" में यह खुलासा किया है कि आज जंगलों पर लगातार दवाब बढ़ता चला जा रहा है और तीन दशकों में 42 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्रों का डायवर्जन हो चुका

है। रिपोर्ट में 92,989 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की भी पहचान की गई है, जो विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत गिरावट से जूझ रही हैं। इसमें 44,891 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का भी उल्लेख किया गया है जो मध्यम सघन वन (एमडीएफ), खुले जंगलों और झाड़ियों से गैर-वन क्षेत्रों में बदल सकते हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यूके स्थित फर्म यूटिलिटी बिडर के मुताबिक वन विनाश के मामले में भारत, ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पर है, जहां पिछले पांच वर्षों में 668,400 हेक्टेयर में फैले जंगल काट दिए गए हैं। यहां पाठकों को यह भी बताता चलूं कि वर्ष 2020 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के करीब 31 फीसदी भूभाग यानी करीब 410 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर जंगल मौजूद हैं। पिछले दशक के आंकड़ों पर नजर डाले तो दुनिया के कई देश ऐसे भी हैं, जिन्होंने वन विनाश को रोकने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है।

गौरतलब है कि इन देशों में भारत भी शामिल है।रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि जहां 2010 से 2020 के बीच चीन के वन क्षेत्र में सालाना 19,37,000 हेक्टेयर की दर से इजाफा हुआ है। वहीं ऑस्ट्रेलिया इस मामले में दूसरे स्थान पर हैं जहां इस दौरान वन क्षेत्र में प्रति वर्ष 446,000 हेक्टेयर की दर से बढ़ोतरी हुई है। वहीं 266,000 हेक्टेयर प्रति वर्ष के साथ भारत तीसरे और 149,000 हेक्टेयर प्रति वर्ष के साथ चिली चौथे स्थान पर है। बहरहाल, आज जब दुनिया भर में पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर कॉप व अन्य जलवायु सम्मेलनों में लगाया बहसें छिड़ीं हैं और हर तरफ चिंता और फिक्र का माहौल है, ऐसे में भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की भारत वन स्थिति रिपोर्ट का यह खुलासा करना कि देश के वनों और वृक्षों के आवरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, वाकई पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिहाज से कुछ उम्मीदें जगाता है, क्यों कि आज हम देख रहे हैं आज किस प्रकार से दिल्ली जैसे मेट्रो शहर लगातार पाल्यूशन की घोर गिरफ्त में आते चले जा रहे हैं।

सभी जानते हैं कि हाल ही में ही में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का 28वें सम्मेलनसंयुक्त अरब अमीरात के दुबई में संपन्न हुआ, जिसमें 197 देशों के प्रतिनिधियों ने 'ग्लोबल वार्मिंग' को रोकने के लिये अपनी पहलों को प्रस्तुत किया और भविष्य की जलवायु कार्रवाइयों पर चर्चा में भागीदारी की थी और भारत ने भी अपनी ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है। हाल फिलहाल, वर्तमान में आई रिपोर्ट कहीं न कहीं यह भी दर्शाती है कि आज भारत सरकार जलवायु संकट के मद्देनजर लगातार सकारात्मक, ठोस और प्रभावी कदम उठा रही है। आज देश का एक चौथाई हिस्सा हरितिमा और हरियाली से भरपूर हो गया है तो यह देश में पर्यावरण के प्रति विशेष उम्मीदें इसलिए जताता है क्यों कि वर्ष 1988 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पारिस्थितिकीय संतुलन व स्थिरता के लिए देश के फुल भौगोलिक क्षेत्र का कम से कम 33 फीसदी भाग वन क्षेत्र होना आवश्यक है। बहरहाल, बावजूद इसके आज देश को वनों की अवैध और अंधाधुंध कटाई, शहरीकरण और खनन गतिविधियां आदि पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। यह ठीक है कि आज विकास बहुत जरूरी है लेकिन विकास और पर्यावरण के बीच आज समन्वय स्थापित करने की जरूरत है।

सुनील कुमार महला

नए साल पर दिल्ली के रेस्तरां और होटलों को मिला ये सख्त आदेश, उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ होगा लाइसेंस रद

नए साल के जश्न के लिए रेस्तरां और होटलों में होने वाली भीड़ को देखते हुए MCD ने सख्त आदेश जारी किए हैं। निगम ने सभी 12 जोन के क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे रेस्तरां और होटलों पर नजर रखें जहां नियमों का उल्लंघन हो रहा है। नियमों का उल्लंघन करने पर रेस्तरांऔर होटल का लाइसेंस निरस्त करने का आदेश दिया।

नई दिल्ली। नए साल के जश्न में रेस्तरां और होटलों में उमड़ने वाली भीड़ के मद्देनजर एमसीडी ने आदेश जारी कर इसकी निगरानी करने के आदेश दिए हैं। इस दौरान किसी रेस्तरां में तय मात्रा से ज्यादा लोग न हो और गैर लाइसेंसकृत भूमि पर व्यावसायिक गतिविधियां आयोजित न हो।

निगम के जन स्वास्थ्य अधिकारी ने निगम के सभी 12 जोन के क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी को आदेश जारी किया है। इसमें ऐसे रेस्तरां और होटलों पर नजर रखने के आदेश दिए गए हैं।

जहां नए साल के जश्न में नियमों का उल्लंघन हो रहा हो। ऐसा पाए जाने पर निगम रेस्तरां और होटल का लाइसेंस निरस्त करने के साथ ही जुर्माना भी लगा सकता है।

2500 से ज्यादा रेस्तरां व होटल एमसीडी इलाके में लाइसेंस कृत

एमसीडी के अनुसार 2500 से अधिक रेस्तरां व होटल एमसीडी इलाके में लाइसेंस कृत हैं। इन होटलों व रेस्तरां में निगम विशेष तौर पर निगरानी रखेगा। इसके साथ ही गैर लाइसेंस रेस्तरां आदि का संचालन न हो इसको भी कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा।

निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हम रेस्तरां को लाइसेंस वहां की सीटिंग क्षमता के आधार पर देते हैं। ऐसे में जरुरी है कि जो सीटें लाइसेंस में उल्लेखित हैं उतनी ही संख्या में लोग वहां पर रहे। उन्होंने बताया कि देखने में आया है कि वर्षांत में होने वाले

आयोजनों में रेस्तरां में लोगों की भीड़ बढ़ जाती है।

सभी रेस्तरां की निगरानी का निर्णय

इससे यह भी संभावना रहती है कि तय सीटों की संख्या से ज्यादा लोगों को रेस्तरां संचालक मुनाफे कमाने के चलते अनुमति दे दें। इससे खाने की गुणवत्ता के साथ ही रेस्तरां की सुरक्षा भी प्रभावित होती है।

इसलिए हमने सभी रेस्तरां की निगरानी का निर्णय लिया है। नव वर्ष तक हमारे अधिकारी इनका निरीक्षण करेंगे ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। साथ ही नियमों का पालन भी हो।

इन इलाकों में बड़े रेस्तरां

उल्लेखनीय है कि दक्षिणी दिल्ली में हौजरानी, छत्तरपुर, लाजपत नगर, वंसत कुंज ग्रेटर कैलाश, मालवीय नगर, ग्रीन पार्क, महिपालपुर, सीआर पार्क जैसे इलाकों में बड़ी मात्रा में रेस्तरां हैं।

इसी प्रकार पूर्वी दिल्ली में लक्ष्मी नगर, कड़कड़डूमा, प्रीत विहार, आनंद विहार, विश्वासन नगर, विकास मार्ग पश्चिमी दिल्ली नजफगढ़, पंचशील, द्वारका, जनकपुरी , तिलक नगर, मोती नगर, राजौरी गार्डन और उत्तम नगर।

वहीं, मध्य दिल्ली में दरियागंज, चांदनी चौक, करोल बाग, कमला नगर, पहाड़रगंज जैसे इलाकों में बड़ी संख्यां में रेस्तरां संचालित होते हैं। जहां वर्षांत में लोग दोस्तों व परिवार के साथ जाते हैं।

दिल्ली चुनाव में जदयू की एंट्री? केजरीवाल के इन बयानों के खिलाफ आक्रमक हुई नीतिश कुमार की पार्टी

जनता दल यूनाइटेड ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर पूर्वांचल के लोगों का अपमान करने का आरोप लगाया है। पार्टी पूर्वांचलियों को लेकर उनके पूर्व के विवादित बयानों का वीडियो क्लीप बनाकर जनता के बीच जाएगी। केजरीवाल ने बिहार के लोगों को दिल्ली पर बोझ बताया था और पूर्वांचल के लोगों को उत्तर प्रदेश की सीमा पर छोड़ दिए जाने की बात कही थी।

नई दिल्ली। जनता दल यूनाइटेड ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पर पूर्वांचल के लोगों का अपमान करने का आरोप लगाया है। पूर्वांचलियों को लेकर उनके पूर्व के विवादित बयानों का वीडियो क्लीप बनाकर जनता के बीच जाएगी पार्टी। प्रेसवार्ता में कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा, केजरीवाल का बिहार के लोगों की क्या भावना है यह सभी जानते हैं। बिहार के लोगों को उन्होंने दिल्ली पर बोझ बताया था।

अन्ना आंदोलन से राजनीति में आए-राजीव रंजन सिंह : केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा पिछले कुछ समय से केजरीवाल का पूर्वांचलियों से प्रेम दर्शा रहे हैं। सच्चाई है कि वह मौकापरस्त है। अन्ना आंदोलन से राजनीति में आए। उसके बाद भ्रष्टाचार के आरोप में घिर गए।

बिहार के लोगों को कहते थे कि पांच सौ का टिकट लेकर आते हैं और पांच लाख का उपचार कराकर वापस चले जाते हैं। करोना महामारी के समय पूर्वांचल के लोगों को उत्तर प्रदेश की सीमा पर छोड़ दिए दें।

पूर्वांचल के लोगों से वह नफरत करते हैं-JDU : आप सरकार ने पूर्वांचल के लोगों को करोना संकट में कोई मदद नहीं की। पूर्वांचल के लोगों से वह नफरत करते हैं। बिहार के लोगों के विरोध में उनके पुराने बयान के वीडियो को लेकर जनता दल यूनाइटेड पूरी दिल्ली में जनता के बीच जाएगी। केजरीवाल का पूर्वांचल के लोगों के प्रति चुनाव के समय यह प्रेम मात्र दिखावा है। उन्होंने पूर्वांचलियों की तुलना रोहिंग्या से कर दिया है।

आंबेडकर को लेकर केजरीवाल ने नीतिश कुमार को लिखा पत्र

आंबेडकर को लेकर उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखे हैं। नीतीश कुमार को केजरीवाल से नैतिकता सीखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा दिल्ली विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ मिलकर लड़ेंगे। इस संबंध में भाजपा से अभी बात चल रही है।

बांग्लादेशी घुसपैठियों के फर्जी आधार और वोटर कार्ड बनाने वाले बड़े गिरोह का भंडाफोड़, 12 गिरफ्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों के दौरान आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आरोपित आम आदमी पार्टी से निलंबित पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। ताहिर ने तीन दिसंबर को उनकी जमानत याचिका खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को उच्च अदालत में चुनौती दी है।

नई दिल्ली। दिल्ली दंगों के दौरान आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में आरोपित आम आदमी पार्टी से निलंबित पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता की पीठ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। ताहिर ने परिस्थितियों में बदलाव के अभाव में तीन दिसंबर को उनकी जमानत याचिका खारिज करने के तीन दिसंबर के ट्रायल कोर्ट के निर्णय को चुनौती दी है।

114 में से अब तक 20 अभियोजन गवाहों से हो चुकी पूछताछ

ताहिर हुसैन ने कहा कि मामले में मुकदमा शुरू हो गया है और 114 में से अब तक 20 अभियोजन गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है। ताहिर की तरफ से पेश अधिवक्ता तारा नरुला ने तर्क दिया कि वह गत चार साल और नौ महीने से जेल में हैं।

वकील तारा नरूला ने कहा कि गवाहों की लंबी फेहरिस्त होने के कारण ताहिर को लंबे समय तक कारावास का सामना करना पड़ा है। यह भी कहा कि मुकदमा जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है और मामले में सह-अभियुक्तों को हाई कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है।

ये है पूरा मामला

दिल्ली में 26 फरवरी 2020 को शिकायतकर्ता रविंदर कुमार ने दयालपुर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को सूचित किया कि आईबी में तैनात उनका बेटा अंकित शर्मा 25 फरवरी से लापता है।

बाद में पता चला कि एक व्यक्ति की हत्या करके चांद बाग पुलिया की मस्जिद के पास से खजूरी खास नाले में फेंक दिया गया है। अंकित शर्मा का शव खजूरी खास नाले से बरामद किया गया था और उनके शरीर पर 51 चोटें थीं।

ताहिर हुसैन को AIMIM ने दिया टिकट

यहां आपको बता दें कि दिल्ली में अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने अपने-अपने उम्मीदवारों की घोषणा करना शुरू कर दिया है। AAP ने तो सभी सीटों पर उम्मीदलार उतार दिए हैं।

इसी क्रम में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को चुनावी मैदान में उतारा है। ओवैसी ने ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद सीट से टिकट दिया है। हाल ही में ताहिर हुसैन के परिवार ओवैसी से मुलाकात भी की थी।

दिल्ली चुनाव से पहले बाहर आएंगे ताहिर हुसैन? जमानत याचिका पर दिल्ली HC ने पुलिस को दिया नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों के दौरान आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आरोपित आम आदमी पार्टी से निलंबित पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। ताहिर ने तीन दिसंबर को उनकी जमानत याचिका खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को उच्च अदालत में चुनौती दी है।

नई दिल्ली। दिल्ली दंगों के दौरान आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में आरोपित आम आदमी पार्टी से निलंबित पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता की पीठ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। ताहिर ने परिस्थितियों में बदलाव के अभाव में तीन दिसंबर को उनकी जमानत याचिका खारिज करने के तीन दिसंबर के ट्रायल कोर्ट के निर्णय को चुनौती दी है।

114 में से अब तक 20 अभियोजन गवाहों से हो चुकी पूछताछ

ताहिर हुसैन ने कहा कि मामले में मुकदमा शुरू हो गया है और 114 में से अब तक 20 अभियोजन गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है। ताहिर की तरफ से पेश अधिवक्ता तारा नरुला ने तर्क दिया कि वह गत चार साल और नौ महीने से जेल में हैं।

वकील तारा नरूला ने कहा कि गवाहों की लंबी फेहरिस्त होने के कारण ताहिर को लंबे समय तक कारावास का सामना करना पड़ा है। यह भी कहा कि मुकदमा जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है और मामले में सह-अभियुक्तों को हाई कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है।

ये है पूरा मामला

दिल्ली में 26 फरवरी 2020 को शिकायतकर्ता रविंदर कुमार ने दयालपुर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को सूचित किया कि आईबी में तैनात उनका बेटा अंकित शर्मा 25 फरवरी से लापता है।

बाद में पता चला कि एक व्यक्ति की हत्या करके चांद बाग पुलिया की मस्जिद के पास से खजूरी खास नाले में फेंक दिया गया है। अंकित शर्मा का शव खजूरी खास नाले से बरामद किया गया था और उनके शरीर पर 51 चोटें थीं।

ताहिर हुसैन को AIMIM ने दिया टिकट

यहां आपको बता दें कि दिल्ली में अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने अपने-अपने उम्मीदवारों की घोषणा करना शुरू कर दिया है। AAP ने तो सभी सीटों पर उम्मीदलार उतार दिए हैं।

इसी क्रम में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को चुनावी मैदान में उतारा है। ओवैसी ने ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद सीट से टिकट दिया है। हाल ही में ताहिर हुसैन के परिवार ओवैसी से मुलाकात भी की थी।

कांग्रेस ने जारी की 26 और प्रत्याशियों की लिस्ट, सिसोदिया के खिलाफ इन्हें मैदान में उतारा

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है। 21 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट 12 दिसंबर को जारी की थी। वहीं आज 26 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। सिसोदिया के खिलाफ कांग्रेस फरहाद सूरी को मैदान में उतारा है। वहीं सीएम आतिशी के खिलाफ ग्रेटर कैलाश से चुनाव कौन लड़ेगा इसका खुलासा नहीं हुआ।

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 26 प्रत्याशियों के नाम हैं। कांग्रेस ने पहली लिस्ट 12 दिसंबर को जारी की थी। कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है। इस बार की सूची में सिसोदिया के खिलाफ कौन होगा, उस प्रत्याशी का नाम पता चल गया है।

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया इस बार जंगपुरा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब तक वो पटपड़गंज सीट से चुनाव लड़ते हैं। इस बार आप ने अवध ओझा को इस सीट से टिकट दिया है। वहीं, कांग्रेस ने सिसोदिया के खिलाफ फरहाद सूरी को मैदान में उतारा है।

अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके खिलाफ संदीप दीक्षित मैदान में हैं। वहीं, हाजी इशराक खान आम आदमी पार्टी से वर्ष 2015 में सीलमपुर के विधायक रहे। मौजूदा समय में इस सीट से आप ने टिकट नहीं दिया तो वो कांग्रेस में चले गए। अब आप के प्रदेश संयोजक व मंत्री गोपाल राय को चुनौती देंगे।

दूसरी लिस्ट के प्रत्याशी

रिठाला- सुशांत मिश्रा
मंगोल पुरी (एससी)- हनुमान चौहान
शकूर बस्ती- सतीश लूथरा
त्रिनगर सतेंद्र- शर्मा
मटिया महल- आसिम अहमद खान
मोती नगर- राजेंद्र नामधारी
मादीपुर (एससी)- जेपी पंवार
राजौरी गार्डन- धर्मपाल चंदेला
उत्तम नगर- मुकेश शर्मा
मटियाला- रघुविंदर शौकीन
बिजवासन- देवेन्द्र सहरावत
दिल्ली कैंट- प्रदीप कुमार उपमन्यु
राजिंदर नगर- विनीत यादव
जंगपुरा- फरहाद सूरी
मालवीय नगर- जितेंद्र कुमार कोचर
महरौली- पुष्पा सिंह
देवली- एससी राजेश चौहान
संगम विहार- हर्ष चौधरी
त्रिलोकपुरी (एससी)- अमरदीप कोंडली (एससी)- अक्षय कुमार
लक्ष्मी नगर- सुमित शर्मा
कृष्णा नगर- गुरचरण सिंह राजू
सीमापुरी (एससी)- राजेश लिलोठिया
बाबरपुर- हाजी मोहम्मद इशराक खान
गोकलपुर (एससी)- प्रमोद कुमार जयंत
करावल नगर- डॉ. पीके मिश्रा

पहली लिस्ट के प्रत्याशी

संदीप दीक्षित- नई दिल्ली
देवेंद्र यादव – बादली
रोहित चौधरी – नांगलोई
रागिनी नायक – वजीरपुर
अभिषेक दत्त – कस्तूरबा नगर
अनिल चौधरी – पटपड़गंज
मुदित अग्रवाल – चांदनी चौक
हारून यूसुफ – बल्लीमारान
अली मेहंदी – मुस्तफाबाद
अब्दुल रहमान – सीलमपुर (मौजूदा विधायक)
आदर्श शास्त्री- द्वारका
अरुणा कुमारी- नरेला
मंगेश त्यागी- बुराड़ी
शिवांक सिंघल- आदर्श नगर
जयकिशन- सुल्तानपर माजरी (एससी)
प्रवीण जैन- शालीमार बाग
अनिल भारद्वाज- सदर बाजार
पीएस बावा- तिलक नगर
राजेंद्र तंवर- छतरपुर
जय प्रकाश- अंबेदकर नगर (एससी)
गर्वित सिंघवी- ग्रेटर कैलाश

जिला कांग्रेस कमेटियों ने बाबा साहेब आंबेडकर सम्मान मार्च निकालकर अपने-अपने क्षेत्रों के जिला अधिकारियों को महामहिम राष्ट्रपति महोदय नामदेय अमित शाह के इस्तीफे का मांग पत्र सौंपा

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव के नेतृत्व में सभी 14 जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों और पदाधिकारियों ने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम क्षेत्रीय जिला अधिकारियों को मांग पत्र सौंपे।

ज्ञातव्य है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब डा0 भीमराव आंबेडकर पर गई आपत्तिजनक और असम्मानजनक टिप्पणी करके पूरे देशवासियों का अपमान किया है जिसका कांग्रेस पार्टी के लगातार विरोध कर रही है और इसी की कड़ी में सभी जिला कांग्रेस कमेटियों, विधानसभा और ब्लाकों में बाबा साहेब आंबेडकर सम्मान मार्च निकाले गए। मार्च में शामिल प्रतिभागियां ने बाबासाहेब डा0 अंबेडकर की तस्वीर, पोस्टर और अमित शाह के इस्तीफे की मांग और अमित शाह देश से माफी मांगे आदि नारों लिखी तख्तियां ली हुई थी।

बाबा साहेब आंबेडकर सम्मान मार्च निकालने के बाद रोहिणी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने अलीपुर स्थित जिला अधिकारी को, करावल नगर जिला अध्यक्ष आदेश भारद्वाज ने नंद नगरी जिला अधिकारी

सहित चॉदनी चौक जिला, आदर्श नगर जिला, बाबरपुर जिला, नई दिल्ली जिला और करोल बाग जिला, तिलक नगर जिला, नजफगढ़ जिला, किराड़ी जिला, कृष्णा नगर जिला, पटपड़गंज जिला, महरौली जिला और बदरपुर जिला के अध्यक्ष श्री विष्णु अग्रवाल के साथ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम गृहमंत्री के इस्तीफे का मांग पत्र सौंपा।

यादव ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह के डा0 अम्बेडकर के खिलाफ अपमानजनक बयान पर प्रधानमंत्री मोदी देश से माफी मांगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आजादी से पहले और आजादी के बाद देश के दलितों, वचिंतो, पिछड़ों और पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति के अधिकारों, हकों और उनके जीवन शैली को बेहतर बनाने लिए प्रतिबद्ध है और संविधान के अंतर्गत डा0 आंबेडकर के विचारों और समाज से विमुख वर्ग के लिए जो उन्होंने प्रावधान और प्रस्ताव रखे उन्हें आज भी उतना ही महत्व देती है जितना आजादी के वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरु ने देश का प्रधानमंत्री रहते हुए दिया था।

उन्होंने कहा कि हमारे नेता पिछले कई वर्षों से देश की 95 प्रतिशत जनसंख्या के अधिकारों और संविधान की रक्षा और सुरक्षा की लड़ाई संसद से सड़क तक तानाशाह सरकार के खिलाफ लड़ रहे है। बाबा साहेब ने दलितों, वचिंतों को बराबरी का हक सुरक्षित रखने के लिए संविधान में जो अधिकार दिए थे, राहुल जी उनकी को बरकरार रखने और भाजपा द्वारा हर दिन उन्हें छीनने के प्रयास के लिए जो संघर्ष कर रहे है उसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ता उनके साथ ढाल बनकर खड़ा है।

यादव ने कहा कि दलितों, वंचितों, गरीबों, पिछड़ों को बराबरी का हक दिलाने वाले बाबा साहेब का अपमान करने के बाद पूरा देश एकजुट होने पर भाजपा डरती हुई दिखाई देती है। जहां भाजपा साम्प्रदायिक राजनीति के सहारे, राहुल पर केस दर्ज कराकर उन्हें प्रताड़ति करने की कोशिश कर रही है उससे राहुल को देश वासियों के लिए संघर्ष करने हेतू अधिक ताकत मिलती है और जितना भाजपा उन्हें दबाने की कोशिश करेगी, राहुल गांधी को अधिक मजबूती मिल रही है।

उन्होंने कहा कि यह पहली बार नही है जब भाजपा ने अम्बेडकर का सार्वजनिक अपमान किया है, बाबा साहेब की फोटो के साथ खिलवाड़ करना करना भाजपा की मनुवादी सोच का परिणाम है। कहीं अम्बेडकर की मूर्ति गिराई जाती है, कहीं उनकी मूर्ति तोड़ी जाती है, उसी सोच के चलते अमित शाह ने संसद में बाबा साहेब का अपमान करते है। और इसी सोच के तहत भाजपा देश के संविधान को बदलना चाहती है, लेकिन करोड़ों लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए संविधान को बदलने की ताकत किसी में नही है।

बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सोपा

सुषमा रानी

पूर्वी दिल्ली गृहमंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक बयान के ख़िलाफ़ बीएसपी के राष्ट्रीय कॉर्डिनेटर आकाश आनद पूर्वी दिल्ली की पूर्व प्रत्याशी वक़ार चौधरी के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओ ने प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को डीएम के माध्यम से ज्ञापन सौंपा

बीएसपी के राष्ट्रीय कॉर्डिनेटर आकाश आनंद ने कहा कि बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेंगे और आज कल हर किसी ने नीली शर्ट और साड़ी पहन कर आपने आप को बाबा साहेब का अनुयायी बताने के ढोंग कर रहे है जबकि ये लोग सबसे ज़्यादा उपेक्षा दलित समाज के लोगो की करते है

इस मौके पर बीएसपी पूर्वी दिल्ली के पूर्व प्रत्याशी वक़ार चौधरी ने कहा की अमित शाह का बयान निंदनीय है और उन्हें देश से माफ़ी माँगनी चाहिए ।

बता दे आज पूरे देश में बहन कुमारी मायावती के निर्देश पर बसपा के लोगो ने प्रदर्शन किया और जगह जगहा डीएम को ज्ञापन दिया नंद नगरी डीएम कार्यालय में हजारों कार्यकर्ताओं ने हाथो में तख्ती बैनर लेकर प्रदर्शन किया जिसे मुख्य रूप से दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष सतीश चौधरी , सलीम अहमद, पूर्व मंत्री धर्मवीर अशोक, डा मुकेश बाला , जुगल जाटव आदि लोग मौजूद रहे।

नोएडा एयरपोर्ट के निकट अवैध कॉलोनियों का विस्तार: विकास योजनाओं पर संकट

इशिका मुख्य रिपोर्टर

ग्रेटर नोएडा। जेवर क्षेत्र में निर्माणाधीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास अवैध कॉलोनियों का तेजी से विस्तार हो रहा है, जो सरकार की विकास योजनाओं के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है।

दयानतपुर गांव बना अवैध निर्माण का केंद्र

एयरपोर्ट से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित दयानतपुर गांव अवैध कॉलोनियों के विस्तार का मुख्य केंद्र बन गया है। यहां बड़े पैमाने पर बिना वैधानिक अनुमति के निर्माण कार्य जारी हैं, जिससे क्षेत्र की योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया बाधित हो रही है।

प्रस्तावित एक्सप्रेसवे के निकट तेजी से बस रही अवैध कॉलोनियां

बल्लभगढ़ से जयपुर एयरपोर्ट तक प्रस्तावित एक्सप्रेसवे के निकट इन अवैध कॉलोनियों का विकास तेजी से हो रहा है। कॉलोनाइजर और प्राइवेट बिल्डर स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापनों के माध्यम से लोगों को यहां बसने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिसमें टीवी, रेडियो और अखबारों का उपयोग किया जा रहा है।

महत्वाकांक्षी योजनाओं पर पड़ सकता है असर

यमुना प्राधिकरण ने एयरपोर्ट के पास फाइव स्टार, श्री स्टार और अन्य होटल परियोजनाओं सहित अमेरिकी, कोरियाई और जापानी सिटी बसाने की योजना बनाई है। लेकिन अवैध कॉलोनियों का यह विस्तार इन योजनाओं के लिए बाधा बन सकता है। यदि जल्द ही इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, तो यह क्षेत्र अनियंत्रित और अव्यवस्थित तरीके से विकसित हो सकता है।

मास्टर प्लान पर संकट

जेवर टोल प्लाजा और एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में अवैध कॉलोनियों का विस्तार तेजी से हो रहा है। राया, टप्पल, बाजना, पलवल और अलीगढ़ जैसे अधिसूचित क्षेत्रों में भी अवैध निर्माण कार्य जोर-शोर से चल रहे हैं। दनकौर से लेकर अलीगढ़ तक इन कॉलोनियों के फैलने से यमुना प्राधिकरण के मास्टर प्लान पर सवाल खड़े हो गए हैं।

प्राधिकरण की कार्रवाई

अवैध निर्माणों को रोकने के लिए यमुना प्राधिकरण ने कुछ कदम उठाए हैं। हाल ही में, प्राधिकरण ने जेवर एयरपोर्ट के पास अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर 15,000 वर्गमीटर जमीन पर किए गए अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस समस्या को समय रहते नहीं रोका गया, तो क्षेत्र की योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया बाधित हो सकती है और मास्टर प्लान में रद्दागद्द के समान होगी। अतः आवश्यक है कि यमुना प्राधिकरण अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कदम उठाए और क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करे।

इस संदर्भ में, यमुना प्राधिकरण ने में भूमि उपयोग में बड़ा बदलाव करते हुए एयरपोर्ट के समीप क्षेत्र को औद्योगिक सेक्टर में परिवर्तित कर दिया है, ताकि अनाधिकृत निर्माणों को रोका जा सके।

इसके अतिरिक्त, यमुना प्राधिकरण ने नोएडा एयरपोर्ट के पास निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए 6,000 प्लॉट की किफायती आवास योजना शुरू करने की पहल की है, जिससे अवैध कॉलोनियों के विस्तार को नियंत्रित किया जा सके।

इन प्रयासों के बावजूद, अवैध कॉलोनियों का विस्तार जारी है, जो क्षेत्र के समग्र विकास और सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है। अतः आवश्यक है कि संबंधित प्राधिकरण और सरकार इस दिशा में और

किसानों के हक की लड़ाई तेज: राकेश टिकैत का 30 दिसंबर को गौतमबुद्ध नगर में पंचायत का ऐलान

इशिका मुख्य रिपोर्टर

मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर के सिसौली स्थित किसान भवन में सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर 'युवा संवाद 3.0' कार्यक्रम और मासिक पंचायत का आयोजन किया गया। इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और राजस्थान के किसान प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

गन्ने के मूल्य में वृद्धि की मांग

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, चौधरी नरेश टिकैत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने कुछ अच्छे कार्य किए हैं, जैसे दिन में बिजली आपूर्ति और एकमुश्त समाधान योजना। हालांकि, गन्ने का आधा सीजन बीत चुका है, लेकिन अभी तक मूल्य घोषित नहीं हुआ है। उन्होंने बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए गन्ने का मूल्य ₹500 प्रति क्विंटल घोषित करने की मांग की।

सरकार की नीतियों का विरोध जारी रहेगा

राष्ट्रीय प्रवक्ता, चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों का पुरजोर विरोध किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नए कानून लाकर किसानों के अधिकारों पर प्रहार कर रही है। गौतमबुद्ध नगर में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ धरना दे रहे किसानों को जेल में बंद कर दिया गया है। इस संदर्भ में, 30 दिसंबर को गौतमबुद्ध नगर के जीरो पॉइंट पर पंचायत आयोजित की जाएगी।

7 जनवरी को जिला मुख्यालयों पर पंचायतें

राकेश टिकैत ने बताया कि देशभर के किसान एमएसपी गारंटी कानून सहित अन्य मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछले 28 दिनों से आमरण अनशन पर हैं, लेकिन सरकार उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। इन मुद्दों को लेकर भारतीय किसान यूनियन 7 जनवरी 2025 को देशभर के जिला मुख्यालयों पर पंचायतें आयोजित करेगी और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेगी।

इन आयोजनों के माध्यम से किसान नेता सरकार की नीतियों के खिलाफ अपने विरोध को और तेज करने की तैयारी में हैं, जिससे किसानों के हक की लड़ाई को मजबूती मिल सके।

दिल्ली में हत्या, फिर कार में शव लेकर घूमे और नोएडा में फेंका... बेटी के प्यार में बाधा बन रही मां को प्रेमी ने मार डाला

एक विवाहित महिला की हत्या कर दी गई और उसका शव नोएडा में फेंक दिया गया। पुलिस ने जांच के बाद खुलासा किया कि महिला की बेटी के प्रेमी ने उसकी हत्या की है। प्रेमी भी जेल में बंद था और महिला की बेटी उससे शादी करना चाहती थी। मां इस शादी का विरोध कर रही थी जिसके चलते प्रेमी ने दो साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी।

ग्रेटर नोएडा। तिहाड़ जेल में बंद पति से मिलने आने वाली महिला का एक युवक से प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। प्रेमी भी जेल में बंद अपने भाई से मिलने आया करता था, जहां दोनों में जान-पहचान हो गई थी। दोनों जेल के बाहर मिलने के बाद एक-दूसरे के घर भी आने-जाने लगे, इसके बाद दोनों ने शादी करने का मन बना लिया। जब प्रेमिका की मां को प्रेम-प्रसंग और शादी की भनक लगी तो उन्होंने विरोध किया। इसके बाद आरोपी प्रेमी ने दो साथियों के साथ मिलकर मां की हत्या कर दी। फिर शव ईकोटेक प्रथम क्षेत्र में फेंक कर भाग गए।

25 नवंबर को मिला शव, 29 को हुई पहचान

एडीसीपी अशोक कुमार के अनुसार, ईकोटेक प्रथम कोतवाली क्षेत्र में 25 नवंबर को एक 40 वर्षीय महिला का शव मिला था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई थी। पुलिस अज्ञात पर हत्या का केस दर्ज कर जांच कर रही थी। जांच करते-करते 29 नवंबर को मृतका की पहचान दिल्ली के मंगोलपुरी निवासी सुमन पत्नी कालीचरण के रूप में हुई थी।

12 दिसंबर को बेटी ने कराया हत्या का केस

पुलिस को पता चला कि 25 नवंबर को स्वजन ने स्थानीय थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। महिला का शव मिलने पर 12 दिसंबर को मृतका की बेटी ने ईकोटेक थाना पहुंचकर हत्या का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी के फुटेज खंगाले, जिसमें एक आर्टिगा कार सवार संदिग्ध प्रतीत हुए।

CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी को पकड़ा

फुटेज व अन्य तथ्यों के आधार पर दिल्ली के राजीव नगर एक्सटेंशन निवासी आरोपी विक्की उर्फ सतीश को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने दो साथियों के साथ महिला की हत्या का जुर्म कुबूल किया। मुख्य आरोपी को जेल और घटना में शामिल अपचारी (नाबालिग आरोपी) को पकड़ कर बाल सुधार गृह भेजा गया है। जबकि तीसरे फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।

एडीसीपी ने बताया कि मृतका की बेटी का पिता और आरोपी प्रेमी विक्की का भाई भी हत्या के मामले में जेल में बंद था। मृतका की बेटी विक्की से शादी करना चाहती थी। मां शादी का विरोध कर रही थी। क्योंकि पति दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद था। जबकि विक्की का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा है। इसी के चलते दोनों शादी करना चाहते थे।

गुरुग्राम के लोगों के लिए अच्छी खबर, चकाचक होगा एसपीआर

गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) सदर्न पेरिफेरल रोड (एसपीआर) को बेहतर बनाने जा रहा है। वाटिका चौक से एनएच-48 तक के हिस्से को 9.65 करोड़ रुपये की लागत से दुरुस्त किया जाएगा। इससे वाहन चालकों को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी और यात्रियों को सुविधा होगी। इस लेख में खबर के माध्यम से पढ़िए पूरी विस्तार से जानकारी।

गुरुग्राम। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) जल्द ही सदर्न पेरिफेरल रोड (एसपीआर) की स्थिति सुधारने का काम शुरू करने जा रहा है।

प्राधिकरण ने वाटिका चौक से एनएच-48 तक (खेड़की दौला के पास) एसपीआर के सुदृढ़ीकरण और मरम्मत के काम के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं। यह कार्य करीब 9.65 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा।

GMDA यात्रियों की सुविधा के लिए सड़क की करेगा मरम्मत

जीएमडीए के मुख्य अभियंता अरुण धनखड़ ने कहा कि यह गुरुग्राम के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है और यहां भारी ट्रैफिक रहता है। जीएमडीए यात्रियों की सुविधा के लिए इस सड़क की मरम्मत करेगा।

मुख्य कैरिज वे को मजबूत करने के अलावा, इस कारिडोर पर नए स्लिप रोड भी बनाए जाएंगे ताकि इस सड़क पर चलने वाले यात्रियों को और राहत मिल सके। प्राधिकरण ने इस साल की शुरुआत में घाटा से वाटिका चौक तक एसपीआर की विशेष सड़क मरम्मत का काम भी करवाया था।

वाटिका चौक से एनएच 48 तक बनेगा सिग्नल फ्री कॉरिडोर

सदर्न पेरिफेरल रोड (एसपीआर) के उन्नयन की योजना भी जीएमडीए द्वारा बनाई गई है, जिसमें वाटिका चौक से एनएच 48-सीपीआर तक एक सिग्नल फ्री कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। जो कुशल गतिशीलता के लिए यातायात का दीर्घकालिक समाधान प्रदान करने में सहायक होगा।

एलिवेटेड रोड का निर्माण हो जाने पर वाहनों के लिए एक अतिरिक्त मार्ग प्रदान करके जमीनी स्तर पर ट्रैफिक को कम करने में मदद मिलेगी और यातायात प्रवाह में सुधार होगा तथा विशेष रूप से व्यस्त समय के दौरान बाधाओं को कम किया जा सकेगा।

वाटिका चौक को एनएच-48 से जोड़ने से गुरुग्राम के दक्षिणी हिस्सों और राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के बीच एक महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी स्थापित होगी, जिससे दिल्ली, जयपुर और शहर के भीतर अन्य प्रमुख गंतव्यों तक आसानी से और तेजी से पहुंच की सुविधा होगी।

साइबर सिटी (Cyber City) और आसपास के इलाकों में विकास की रफ्तार ट्रैफिक के दबाव की वजह से धीरे-धीरे कम होती जा रही है। विकास की रफ्तार बनी ही न रहे, बल्कि तेज हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन की सुविधा को बेहतर करने पर तत्काल जोर देने की जरूरत है। इसे लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साइबर सिटी और आसपास मेट्रो का जाल बिछाने के बारे में 24 दिसंबर को गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) एवं गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) के अधिकारियों के साथ बैठक की।

1000 एकड़ में बनने वाली नोएडा फिल्म सिटी का जनवरी में शुरू होगा काम, एयरपोर्ट से 3 किमी दूर; जानिए पूरा प्रोजेक्ट

ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल फिल्म सिटी बनने जा रही है। बोनी कपूर की कंपनी बेव्यू प्रोजेक्ट्स और भूटानी ग्रुप ने फिल्म सिटी का जिम्मा सभाला है। पहले चरण का काम जनवरी में शुरू हो जाएगा जो तीन वर्ष में पूरा होगा। फिल्म सिटी को एक हजार एकड़ में बनाया जाना है। जानिए फिल्म सिटी की खासियतें और कब तक होगी तैयार।

ग्रेटर नोएडा। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार यमुना प्राधिकरण के सेक्टर-21 में विकसित होने वाली अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी का शिलान्यास जनवरी में किया जाएगा। बोनी कपूर की कंपनी बेव्यू प्रोजेक्ट्स और भूटानी ग्रुप ने इसी वर्ष जुलाई में जमीन पर कब्जा लिया था। मंगलवार को बोनी कपूर ने यमुना प्राधिकरण पहुंचकर फिल्म सिटी का मास्टर प्लान भी सौंप दिया है।

प्राधिकरण ने 24 घंटे में मास्टर प्लान को स्वीकृत करने का भरोसा दिया है। पहले चरण के तहत 230 एकड़ भूमि पर निर्माण शुरू होगा। इसमें से 155 एकड़ में औद्योगिक व 75 एकड़ में व्यावसायिक गतिविधियां होगी।

बोनी कपून सौंपा मास्टर प्लान

मंगलवार को फिल्म निर्माता बोनी कपूर यमुना प्राधिकरण में सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह से मिलने पहुंचे। बैठक में उन्होंने फिल्म सिटी का मास्टर प्लान सौंपा। उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी को प्रथम चरण में विकसित करने का मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। सेक्टर-21 में 1000 एकड़ में फिल्म सिटी प्रस्तावित है।

तीन वर्ष में पूरा हो जाएगा पहला चरण

पहले चरण में 230 और दूसरे में 670 एकड़ भूमि को विकसित किया जाएगा। फिल्म सिटी बनाने के लिए दुनियाभर की कई फिल्म सिटी का अध्ययन किया गया है। दावा किया कि यह अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी विश्व में सबसे अलग होगी। जनवरी में प्रथम चरण के तहत फिल्म सिटी का शिलान्यास कर दिया जाएगा। प्रथम चरण को तीन वर्ष में पूरा किया जाएगा।

अभिनेता और अभिनेत्री के लिए बनेंगे विला

फिल्म सिटी परिसर में अभिनेता अभिनेत्री के रहने के लिए विला भी बनाए जाएंगे। बोनी कपूर ने बताया कि अक्सर अभिनेता और अभिनेत्रियों को होटल में रुकना पड़ता है। विला में उनकी निजता भी सुरक्षित रहेगी। कई बार होटल में प्रशंसक पहुंच जाते हैं, जिससे कलाकारों को शूटिंग में पहुंचने में देर हो जाती है। फिल्म सिटी की एयरपोर्ट से दूरी मात्र तीन किलोमीटर है। विला पहुंचने में देर भी नहीं लगेगी।

पानी के अंदर की शूटिंग की सुविधा

बोनी कपूर ने बताया कि फिल्म निर्माता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए फिल्म सिटी का निर्माण इस तरह किया जाएगा कि उन्हें हर तरह की लोकेशन की सुविधा एक ही छत के नीचे मिल सके। जैसे कि यदि उन्हें समुद्र के अंदर का दृश्य दिखाना है तो उसके लिए विशाल वॉटर टैंक और विशाल पूल बनाया जाएगा। पानी का जहाज होगा। इससे खर्च भी कम होगा।

आधा हो जाएगा फिल्म का बजट

फिल्म बनाने के लिए कई बार विदेश में शूटिंग करनी पड़ती है। कई बार स्पेशल इफेक्ट्स के लिए बाहर से तकनीक की सहायता लेनी पड़ती है। यह सब फिल्म सिटी में मिलेगा, जिससे विदेशों के मुकाबले 50 प्रतिशत कम बजट में फिल्में बन सकेंगी। यहां घूमने आने वाले लोगों के लिए सिनेमा आधारित थीम पार्क बनाए जाएंगे। शॉपिंग सेंटर खुलेंगे।

फिल्म में करियर बनाने को स्कूल व विश्वविद्यालय खुलेंगे। इससे गौतमबुद्धनगर और आसपास के जिलों में पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी। आगरा और मथुरा आने वाले पर्यटक यहां भी आएंगे। एकमात्र ऐसी फिल्म सिटी होगी, जिसमें डिज्नीलैंड एम्यूजमेंट पार्क, फिल्म विश्वविद्यालय के अलावा पांच और सात सितारा होटल बनाए जाएंगे।

संसद की दिखेगी झलक

फिल्म सिटी में संसद की झलक दिखाने के लिए संसद जैसी गैलरी बनाई जाएगी। 800 मीटर से ऊंची इमारतें बनेंगी। ऑडिटोरियम, होटल, विला, वर्चुअल स्टूडियो, फूड कोर्ट समेत स्टूडियो को एलईडी आधारित डिजाइन किया जाएगा, जिससे कि तकनीक के माध्यम से किसी भी प्रकार की लोकेशन को सेट किया जा सके।

पूल में लहरें भी उत्पन्न की जा सकेंगी। सुनामी जैसी स्थिति को भी शूट किया जा सकेगा। फिल्म इंडस्ट्री की जरूरतों के मुताबिक युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए कौशल विकास केंद्र भी खोले जाएंगे।

बोनी कपूर ने कहा कि मुंबई व हैदराबाद की फिल्म सिटी से स्टाफ व विशेषज्ञों को नहीं लाया जाएगा। यहां के लिए अलग से युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। सिनेमा की दुनिया में जो भी अपना नाम कमाना चाहेगा, उसे यहां पर ही प्रशिक्षित किया जाएगा।

प्रथम चरण

फिल्मिंग सुविधाएं: 135 एकड़
फिल्म संस्थान: 20 एकड़
व्यवसायिक गतिविधियां: 75 एकड़
कुल 1510 करोड़ रुपये होंगे खर्च
फिल्म निर्माण के संसाधन पर खर्च: 832.91 करोड़
स्टूडियो, ओपन सेट्स सहित हास्पिटैलिटी: 373.93 करोड़
सर्विस एकोमोडेशन: 315.07 करोड़
यमुना प्राधिकरण उठाएगा यह खर्च
ढांचागत सुविधा: 76.44 करोड़
कार्यालय निर्माण: 109.60 करोड़

मास्टर प्लान को 24 घंटे में स्वीकृत करने की तैयारी है। फिल्म सिटी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अहम परियोजना है। इससे क्षेत्र के विकास में और तेजी आएगी। फिल्म सिटी के लिए कंपनी को 230 एकड़ भूमि पर कब्जा दे दिया है। जनवरी में फिल्म सिटी का निर्माण शुरू हो जाएगा। -डॉ. अरुणवीर सिंह, सीईओ, यमुना प्राधिकरण

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV
Drive the Future

एमजी की जल्द आने वाली है नई सुपर कार Cyberster, स्पेसिफिकेशन का हुआ खुलासा

परिवहन विशेष न्यूज

MG Cyberster की डिटेल्स सामने आई है। इसमें ड्रॉप-टॉप रूफ और सिजर डोर के साथ भारत की सबसे सस्ती रोडस्टर होने की संभावना है। इसे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में लॉन्च किया जा सकता है। वहीं इसकी एक्स-शोरूम कीमत 60 लाख रुपये से 70 लाख रुपये तक हो सकती है। आइए जानते हैं कि एमजी साइबरस्टर किन फीचर्स के साथ आने वाली है।

नई दिल्ली। JSW MG मोटर इंडिया सेलेक्ट के जरिए लग्जरी सेगमेंट में अपनी गाड़ियां लेकर आने वाली है। इसकी शुरुआत कंपनी MG Cyberster को लॉन्च करने वाली है। इसमें 2-डोर इलेक्ट्रिक दिए गए है। वहीं, साइबरस्टर 2-डोर इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार की डिटेल्स भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 से पहले आए हैं। आइए जानते हैं कि MG Cyberster किन खूबियों के साथ भारत में एंट्री मारने वाली है।

MG Cyberster: फीचर्स

भारत दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोटिव बाजारों में से एक बन गया है। घरेलू भारतीय ब्रांडो के अलावा, कई विदेशी कंपनियां अपनी लग्जरी कार लेकर आ रही है। जिसमें से एक MG भी है। इसने MG Cyberster के डिटेल्स को जारी किया है। भारत-स्पेक साइबरस्टर में बड़े 77 kWh बैटरी पैक दिया गया है, जिसकी मदद से यह स्पोर्ट्स कार महज 3.2 सेकंड में 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। इसमें लगी हुई बैटरी AWD लेआउट के लिए दोनों एक्सल पर दो इलेक्ट्रिक मोटर्स को पावर देती है। इसमें लगा हुआ मोटर 510 bhp की पावर और 725 Nm का टॉर्क जनरेट करता है।

यह एक स्पोर्ट्स कार है, जिसकी वजह से Cyberster को उसी तरह से हैंडल करने की जरूरत है। इसके आगे की तरफ डबल विशबोन सस्पेंशन और पीछे की तरफ इंडीपेंडेड मल्टी-लिंक सस्पेंशन दिया गया है।

इसमें सिजर डोर हैं जो बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ खुलते हैं। डैशबोर्ड पर मल्टी-स्क्रीन लेआउट, विशाल सेंटर कंसोल, स्पोर्टी फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील और लेदर अपहोल्स्ट्री जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

इसमें ड्रॉप-टॉप रूफ, फ्रेमलेस विंडो, फुल एलईडी लाइटिंग, बड़े पहिए, एयरोडायनिक के लिए बड़ा अंडरबॉडी डिफ्यूज़र जैसी चीजें दी गई है।

भारत में कब होगी लॉन्च?

JSW MG मोटर इंडिया Cyberster को लॉन्च करने के लिए तैयार है। इसे MG सेलेक्ट प्रीमियम डीलरशिप के जरिए भारत में लाया जाएगा, जो इसकी पहली कार होने वाली है। इसे भारत में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी भारत में एक्स-शोरूम कीमत 60 लाख रुपये से 70 लाख रुपये तक हो सकती है।

सरकार से एआई, ईवी और ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए विशेष रियायतों की मांग

परिवहन विशेष न्यूज

औद्योगिक संगठनों ने आगामी बजट में बैंकों से लोन से जुड़े प्राथमिक क्षेत्रों की सूची में इलेक्ट्रिक व्हीकल, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसे उभरते क्षेत्रों को शामिल करने की मांग की है। फिलहाल लोन से जुड़े प्राथमिक क्षेत्रों में मुख्य रूप से कृषि, शिक्षा, एमएसएमई शामिल हैं।

उद्योग संगठन सीआईआई का कहना है कि जीडीपी ग्रोथ में कृषि की हिस्सेदारी 14 फीसदी है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र के लोन का 18 फीसदी हिस्सा कृषि को दिया जाता है। यह हिस्सेदारी तब तय की गई थी, जब जीडीपी ग्रोथ में कृषि की हिस्सेदारी 30 फीसदी थी। उद्योग जगत का मानना है कि एआई, ग्रीन एनर्जी, ईवी जैसे क्षेत्र दुनिया भर में तेजी से उभर रहे हैं और अगर इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया तो भारत इनमें पिछड़ सकता है।

इससे इन उत्पादों के लिए आयात पर निर्भरता बढ़ेगी। एआई, ग्रीन एनर्जी, ईवी जैसे क्षेत्रों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये कार्बन उत्सर्जन से जुड़े हैं। भारत भी कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग पर आधारित है। अगर इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया तो बड़ी संख्या में रोजगार भी सृजित होंगे।

उद्योग संगठन का कहना है कि लोन से जुड़े प्राइमरी सेक्टर के नियमों में बदलाव जरूरी है और सरकार चाहे तो एक कमेटी भी बना सकती है। उद्यमियों का कहना है कि बजट में सरकार

को इलेक्ट्रिक कारों की खरीद के लिए बैंकों से मिलने वाले लोन में विशेष रियायत देनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की तरह इलेक्ट्रिक कारों की खरीद पर सरकार की ओर से कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार यानी आज आगामी बजट को लेकर अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक भी की। नीति आयोग भवन में होने वाली बैठक में कुछ खास औद्योगिक क्षेत्रों के विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया गया है। बैठक में कुछ केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग की चेयरमैन सुमन बेरी भी शामिल हुईं। बैठक की शुरुआत में नीति आयोग के चेयरमैन और वित्त सचिव ने देश की अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा पर दो अलग-अलग विचार पेश किए। दूसरी तिमाही में देश की आर्थिक विकास दर धीमी पड़ने के बाद इसे अहम माना जा रहा है। सरकार हर आम बजट से पहले ऐसी बैठकों का आयोजन करती है।

उद्योग संगठन का कहना है कि कर्ज से जुड़े प्राथमिक सेक्टर के नियमों में बदलाव जरूरी है और सरकार चाहे तो एक कमेटी का भी गठन कर सकती है। उद्यमियों का कहना है कि बजट में इलेक्ट्रिक कार की खरीदारी के लिए बैंकों से मिलने वाले लोन में सरकार की तरफ से विशेष रियायत मिलनी चाहिए। इसका कारण यह है कि इलेक्ट्रिक कार की खरीदारी पर इलेक्ट्रिक दोपहिया की तरह सरकार से कोई सब्सिडी भी नहीं दी जाती है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजट को लेकर मंगलवार यानी आज अर्थविदों के साथ मीटिंग भी की। नीति आयोग के भवन में होने वाली बैठक में कुछ खास औद्योगिक सेक्टरों के विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया गया है। बैठक में कुछ केंद्रीय मंत्रियों और नीति आयोग के चेयरमैन सुमन बेरी भी शामिल हुए। बैठक के शुरुआत में नीति आयोग के चेयरमैन और वित्त सचिव देश की इकोनॉमी की दिशा व दशा पर दो अलग अलग नजरिया पेश किया।

दूसरी तिमाही में देश की आर्थिक विकास दर की रफ्तार सुस्त होने के बाद इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस तरह की बैठक सरकार हर आम बजट से पहले आयोजित करती है।

ईवी निर्माता ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी 1000 करोड़ रुपये का लाएगी आईपीओ

परिवहन विशेष न्यूज

ग्रीव्स कॉटन की सब्सिडियरी कंपनी ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड ने आईपीओ लाने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दाखिल किया है यानी उसने आईपीओ लाने के लिए सेबी के पास आवेदन किया है। कंपनी इस ऑफर के जरिए 1,000 करोड़ रुपये तक जुटाने की योजना बना रही है, जिसमें नए इक्विटी शेयरों के साथ-साथ ऑफर-फॉर-सेल के जरिए शेयर बेचे जाएंगे। ग्रीव्स कॉटन 5.1 करोड़ शेयर और अब्दुल लतीफ जमील ग्रीन मोबिलिटी सॉल्यूशंस डीएमसीसी के जरिए 13.84 करोड़ शेयर बेचेगी। फिलहाल ग्रीव्स कॉटन के पास कंपनी की 62.48% हिस्सेदारी है, जबकि अब्दुल लतीफ जमील ग्रीन मोबिलिटी सॉल्यूशंस डीएमसीसी के पास 36.44% हिस्सेदारी है।

कंपनी आईपीओ के जरिए जुटाए गए फंड का एक हिस्सा ग्रोथ में खर्च करेगी। भारत में तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर में विस्तार से इसे लाभ मिलने की उम्मीद है। ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपने 'एम्पीयर' ब्रांड के ई-स्कूटर के लिए जानी जाती है और एक अलग ब्रांड के तहत तिपहिया वाहन भी बनाती है।

ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड भारत के उभरते इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में अग्रणी खिलाड़ियों में से एक है और ईवी अपनाने में सबसे आगे रही है। कंपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग के लिए बी2सी और बी2बी ग्राहकों को इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों का एक विविध पोर्टफोलियो प्रदान करती है।

अस्वीकरण: यहां मुख्य रूप से आईपीओ के बारे में जानकारी दी गई है, निवेश सलाह नहीं। इक्विटी मार्केट में जोखिम है, इसलिए अपने जोखिम पर निवेश करें। निवेश करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें।

हुंडई मोटर इंडिया ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी सेल बनाने के लिए एक्साइड इंडस्ट्रीज के साथ की साझेदारी

परिवहन विशेष न्यूज

हुंडई मोटर इंडिया ने भारतीय बाजार के लिए समर्पित एचएमआईएल के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी सेल के उत्पादन और आपूर्ति के लिए एक्साइड इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस के साथ एक बाध्यकारी टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए हैं।

टर्म शीट में एचएमआईएल द्वारा अपने इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग के लिए लिथियम-आयन सेल्स और बैटरी पैक्स के आपूर्तिकर्ता के रूप में ईईएसएल को शामिल करने के इरादे को औपचारिक रूप दिया गया है।

प्रस्तावित व्यवस्था से, एक बार निर्णायक समझौते निष्पादित हो जाने पर, इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास और उत्पादन में तेजी आने की उम्मीद है, जिससे भारत में टिकाऊ परिवहन समाधानों के विकास में योगदान मिलेगा।

गुरुवार, 19 दिसम्बर को एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, दक्षिण कोरिया की हुंडई मोटर कंपनी की भारतीय इकाई, बैटरी सेल को टर्म शीट में निर्धारित मूल्य पर खरीदेगी।

इस टर्म शीट के बाद होने वाले निर्णायक समझौते, इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन में वृद्धि को गति प्रदान करेंगे, तथा देश के हरित ऊर्जा परिवर्तन में योगदान देंगे।

हालांकि इस साझेदारी से होने वाली आय की वास्तविक संभावना का खुलासा होना अभी बाकी है, लेकिन यह समझौता एक्साइड इंडस्ट्रीज के लिए बढ़ते ईवी बाजार का लाभ उठाने का एक आशाजनक अवसर प्रस्तुत करता है। वैश्विक हुंडई मोटर कंपनी समूह की सहायक कंपनी होने के नाते हुंडई मोटर इंडिया पर्याप्त विशेषज्ञता और पैमाने लेकर आती है, जिससे यह सहयोग प्रतिस्पर्धी ईवी क्षेत्र में दोनों कंपनियों के लिए संभावित रूप से परिवर्तनकारी कदम बन जाता है।

यह विकास भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर बढ़ते जोर के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे सरकारी प्रोत्साहनों और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की तत्काल आवश्यकता का समर्थन प्राप्त है। एक साथ मिलकर, एक्साइड और हुंडई न केवल स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं, बल्कि ईवी बैटरी सेगमेंट में बढ़ी हुई घरेलू उत्पादन क्षमताओं का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। यह साझेदारी नवाचार को बढ़ावा देने और विद्युतीकृत भविष्य की मांगों को पूरा करने में उद्योग सहयोग के लिए एक बेंचमार्क स्थापित करती है।

टर्म शीट एक गैर-बाध्यकारी दस्तावेज़ है जो पक्षों के बीच प्रस्तावित समझौते या लेनदेन की मुख्य शर्तों और नियमों को रेखांकित करता है। यह बातचीत के लिए एक खाका के रूप में कार्य करता है, जो दोनों पक्षों को एक निश्चित, कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते में व्यवस्था को औपचारिक रूप देने से पहले आपसी समझ तक पहुँचने में मदद करता है।

ग्रेटर नोएडा के हर व्यावसायिक भवन में बनेंगे ईवी चार्जिंग स्टेशन, प्राधिकरण ने चिह्नित किए 15 स्थान

परिवहन विशेष न्यूज

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने हर व्यावसायिक भवन में ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना तैयार की है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्राधिकरण ने 15 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है। ईवी चार्जिंग स्टेशन संचालित करने वाली कंपनी की तलाश शुरू कर दी गई है। योजना के मुताबिक कंपनी को 10 साल के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। कंपनी इन स्टेशनों से होने वाली आय का एक हिस्सा प्राधिकरण को सौंपेगी।

अधिकारियों के मुताबिक ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती है। 50 मीटर से कम जगह में चार्जिंग स्टेशन बनाए जा सकते हैं। वाहन चालकों की जरूरत के हिसाब से इनमें एक से ज्यादा वाहनों को चार्ज करने के लिए नोजल दिए जाएंगे।

इसके अलावा ई-वॉलेट के जरिए भुगतान की सुविधा दी जाएगी। चार्जिंग स्टेशन के लिए ऐसे स्थानों का चयन किया जा रहा है जहां वाहन ज्यादा संख्या में आते हैं और लंबे समय तक खड़े रहते हैं। ताकि चार्जिंग के दौरान वाहन चालकों को स्टेशन तक पहुंचने में कोई परेशानी न हो और न ही उन्हें चार्जिंग में ज्यादा समय लगे।

इसके लिए सूरजपुर कलेक्ट्रेट, पुलिस

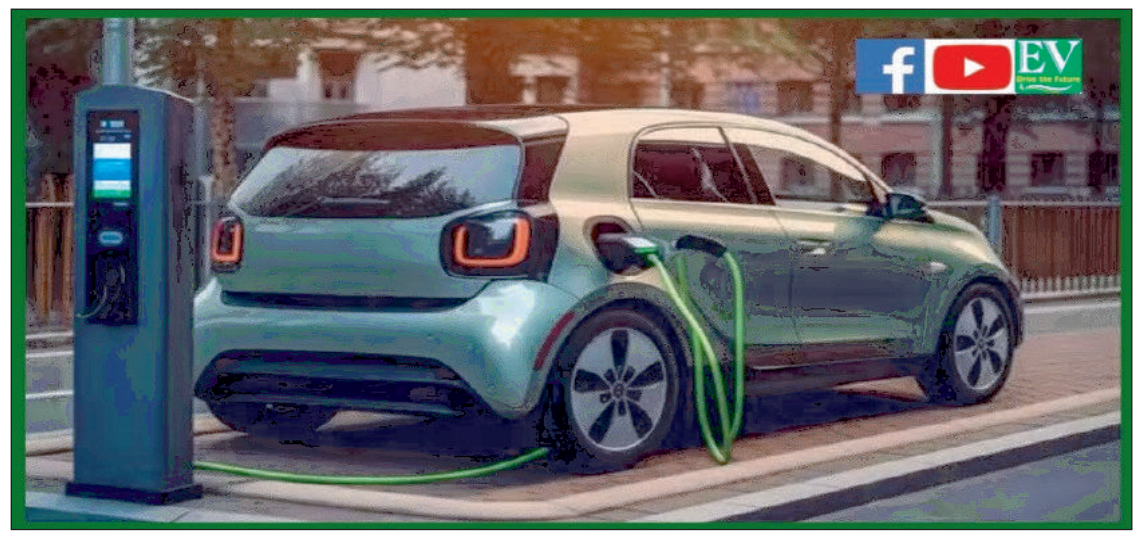

ऑफिस, जिला न्यायालय के पास, कासना, नॉलेज पार्क, सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र, साइट-4, साइट-5, तुगलकपुर, रामपुर जैसे सरकारी दफ्तरों के नजदीक के स्थानों को प्राथमिकता दी गई है। दफ्तरों और पार्किंग की अधिकता को देखते हुए सबसे पहले कमर्शियल बेल्ट को चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए चुना गया है।

पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के क्षेत्र में 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना है। एयरपोर्ट को जोड़ने वाले रूट पर 100 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए जगह चिह्नित की जा रही हैं। बस स्टॉप के पास भी चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना है। ईवी को बढ़ावा देने के लिए 100 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन तैयार करने का निर्णय लिया गया है। इसमें जनवरी तक 15 स्टेशन चालू हो जाएंगे। सभी कमर्शियल बिल्डिंग में चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके लिए शुल्क आदि जल्द ही तय किए जाएंगे। - प्रेरणा सिंह, एसीईओ, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी।

आमतौर पर घरों में उपलब्ध बिजली से वाहनों की चार्जिंग धीमी होती है। यही वजह है कि ज्यादातर ई-वाहनों को रातभर चार्जिंग के लिए छोड़ना पड़ता है। अथॉरिटी की ओर से हर चार्जिंग स्टेशन पर तीन तरह के प्वाइंट बनाए जाएंगे। इनमें स्लो, मीडियम और फास्ट चार्जिंग के विकल्प होंगे। इसमें दोपहिया वाहन 20 मिनट से एक घंटे में और चार पहिया वाहन एक घंटे से ढाई घंटे में फुल चार्ज हो जाएंगे। चार्जिंग में लगने वाले समय के हिसाब से ही शुल्क भी निर्धारित होगा।

टाटा मोटर्स को बीएमटीसी से और अधिक इलेक्ट्रिक बसों का मिला ऑर्डर

परिवहन विशेष न्यूज

भारत की सबसे बड़ी वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से 148 इलेक्ट्रिक बसों का अतिरिक्त ऑर्डर हासिल किया है। टाटा स्टारबस EV12-मीटर लो-फ्लोर इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति, संचालन और रखरखाव का प्रबंधन 12 साल की अवधि में टाटा मोटर्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टीएमएल स्मार्ट सिटी मोबिलिटी सॉल्यूशंस लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।

यह नया ऑर्डर 921 इलेक्ट्रिक बसों के पिछले ऑर्डर पर आधारित है, जिनमें से अधिकांश पहले ही डिलीवर हो चुके हैं और वर्तमान में बीएमटीसी के बेड़े में 95% से अधिक अपटाइम के साथ चल रहे हैं। टाटा स्टारबस ईवी, जो अपने बेहतरीन डिज़ाइन और उन्नत सुविधाओं के लिए जानी जाती है, बेंगलुरु के नागरिकों के लिए एक टिकाऊ और आरामदायक आवागमन का वादा करती है। अगली पीढ़ी की वास्तुकला पर निर्मित और उन्नत बैटरी सिस्टम से लैस, बसें सुरक्षित, कुशल और सुविधाजनक इंट्रा-सिटी यात्रा सुनिश्चित करती हैं।

बीएमटीसी के प्रबंध निदेशक श्री रामचंद्रन आर., आईएएस ने टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक बसों के असाधारण प्रदर्शन को देखते हुए साझेदारी पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 148 और बसों के जुड़ने से बीएमटीसी की पर्यावरण अनुकूल, आरामदायक और विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने की क्षमता में और वृद्धि होगी, जो शहर की सतत शहरी गतिशीलता के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

टीएमएल स्मार्ट सिटी मोबिलिटी सॉल्यूशंस लिमिटेड के सीईओ और एमडी असीम कुमार मुखोपाध्याय ने इस ऑर्डर के महत्व को बेंगलुरू के शहरी परिवेश में टाटा मोटर्स के स्टारबस ईवी की सफलता के प्रमाण के रूप में उजागर किया। उन्होंने समुदाय और पर्यावरण दोनों को लाभ पहुँचाने वाले अभिनव और टिकाऊ मोबिलिटी समाधान प्रदान करने के लिए कंपनी के समर्पण की पुष्टि की।

टाटा मोटर्स की ई-बसें अकेले बेंगलुरु में 2.5 करोड़ किलोमीटर से अधिक की कुल दूरी तय कर चुकी हैं, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 14,000 टन CO_2 उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आई है। यह उपलब्धि कंपनी की स्थिरता, नवाचार और उन्नत गतिशीलता समाधानों के माध्यम से शहरी जीवन को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

44 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कंपनी और टाटा समूह का हिस्सा टाटा मोटर्स भारत के वाणिज्यिक वाहन बाजार में अग्रणी बनी हुई है। एकीकृत और ई-मोबिलिटी समाधानों की विस्तृत श्रृंखला के साथ, कंपनी शहरी परिवहन को बदलने और रकनेक्टिंग एस्पिरेशंसर के अपने ब्रांड वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

देश के अप्रतिम नेता अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत का जश्न

भारतीय राजनीति में उनके योगदान और पारदर्शी और जवाबदेह सरकार के लिए उनके दृष्टिकोण को मान्यता देना। जागरूकता को बढ़ावा देना, नागरिकों को सुशासन के महत्त्व और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भूमिका के बारे में शिक्षित करना। जनता की प्रभावी और नैतिक रूप से सेवा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को मज़बूत करना। इसे किसी संगठन या समाज के भीतर निर्णय लेने और लागू करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। शासन केवल व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही आवश्यक नहीं है; यह उद्देश्यों को प्राप्त करने और समुदाय या समूह की आवश्यकताओं को सम्बोधित करने में भी मदद करता है।

25 दिसम्बर, 2024 का सुशासन दिवस विशेष महत्त्व रखता है क्योंकि यह अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती है। इस मील के पत्थर को मनाने के लिए, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने 19 से 24 दिसम्बर, 2024 तक चलने वाले 'प्रशासन गाँव की ओर' नामक एक सप्ताह के अभियान की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य शासन को जमीनी स्तर पर लाना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रशासनिक सेवाएँ ग्रामीण आबादी तक पहुँच सकें। सुशासन दिवस पारदर्शी, जवाबदेह और लोगों की ज़रूरतों के प्रति उत्तरदायी शासन के महत्त्व की याद दिलाता है। सुशासन सार्वजनिक संसाधनों और संस्थानों को ईमानदारी और निष्पक्ष रूप से, भ्रष्टाचार या सत्ता के दुरुपयोग के बिना प्रबंधित करने की एक प्रक्रिया है। यह सुनिश्चित करता है कि कानूनों का पालन किया जाए, मानवाधिकारों की रक्षा की जाए और समाज की ज़रूरतों को पूरा किया जाए। इसका उद्देश्य नागरिकों की प्रभावी रूप से सेवा करने और शासन प्रक्रिया में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ज़िम्मेदारी के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है।

---डॉ. सत्यवान सौरभ

भारत में हर साल 25 दिसम्बर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस मनाया जाता है। पहली बार 2014 में मनाया गया यह दिवस पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है कि विकास का लाभ हर नागरिक तक पहुँचे। अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रमुख भारतीय राजनेता और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के संस्थापक सदस्य थे। अपनी वाक्पटुता और काव्य कौशल के लिए जाने-जाने वाले, उन्हें उनके उदार राजनीतिक विचारों और आम सहमति बनाने के प्रयासों के लिए पार्टी लाइनों से परे सम्मान दिया जाता था। वाजपेयी का राजनीतिक करियर पाँच दशकों से अधिक समय तक चला, जिसके दौरान उन्होंने भारत की घरेलू और विदेश नीतियों को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा के सम्मान में, उन्हें 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

25 दिसम्बर, 1924 को ग्वालियर, मध्य प्रदेश में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रतिष्ठित राजनेता, कवि और वक्ता थे। उन्होंने तीन बार भारत के प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया और देश के विकास पथ पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनके कार्यकाल में महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुधार, स्वर्णिम चतुर्भुज जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाएँ और भारत की वैश्विक स्थिति में सुधार के प्रयास शामिल थे। वाजपेयी के नेतृत्व की विशेषता लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता थी, जो उनकी जयंती को सुशासन दिवस मनाने का एक उपयुक्त अवसर बनाती है। सुशासन दिवस 2024 न केवल वाजपेयी की विरासत का स्मरण करता है, बल्कि नागरिकों और अधिकारियों से देश के समग्र विकास के लिए पारदर्शी, जवाबदेह और समावेशी शासन को बढ़ावा देने का आग्रह भी करता है।

25 दिसम्बर, 2024 का सुशासन दिवस विशेष महत्त्व रखता है क्योंकि यह अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती है। इस मील के पत्थर को मनाने के लिए, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने 19 से 24 दिसम्बर, 2024 तक चलने वाले 'प्रशासन गाँव की ओर' नामक एक सप्ताह के अभियान की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य शासन को जमीनी स्तर पर लाना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रशासनिक सेवाएँ ग्रामीण आबादी तक पहुँच सकें। सुशासन दिवस पारदर्शी, जवाबदेह और लोगों की ज़रूरतों के प्रति उत्तरदायी शासन के महत्त्व की याद दिलाता है। सुशासन सार्वजनिक संसाधनों और संस्थानों को ईमानदारी और निष्पक्ष रूप से, भ्रष्टाचार या सत्ता के दुरुपयोग के बिना प्रबंधित करने की एक प्रक्रिया है। यह सुनिश्चित करता है कि कानूनों का पालन किया जाए, मानवाधिकारों की रक्षा की जाए और समाज की ज़रूरतों को पूरा किया जाए। इसका उद्देश्य नागरिकों की प्रभावी रूप से सेवा करने और शासन प्रक्रिया में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ज़िम्मेदारी के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है।

भारतीय राजनीति में उनके योगदान और पारदर्शी और जवाबदेह सरकार के लिए उनके दृष्टिकोण को मान्यता देना। जागरूकता को बढ़ावा देना, नागरिकों को सुशासन के महत्त्व और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भूमिका के बारे में शिक्षित करना। जनता की प्रभावी और नैतिक रूप से सेवा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को मज़बूत करना। इसे किसी संगठन या समाज के भीतर निर्णय लेने और लागू करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। शासन केवल व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही आवश्यक नहीं है; यह उद्देश्यों को प्राप्त करने और समुदाय या समूह की आवश्यकताओं को सम्बोधित करने में भी मदद करता है। विश्व बैंक के अनुसार, सुशासन ₹वह तरीक़ा है जिसमें विकास के लिए किसी देश के आर्थिक और सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति का प्रयोग किया जाता है₹। संस्थाओं को इस तरह से संचालित होना चाहिए कि दूसरों के लिए यह देखना आसान हो कि क्या कार्य किए जा रहे हैं। यह भ्रष्ट आचरण को भी रोकता है। शासक वर्ग को लोगों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। इससे लोगों और पूरे समाज की बेहतरी सुनिश्चित होगी।

शासी संस्थाओं को लोगों की चिंताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और उचित समय के भीतर उनकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। समाज के सभी वर्गों के लोगों को बिना किसी भेदभाव के सुधार के लिए समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। निर्णय समाज के एक बड़े वर्ग की सहमति से लिए जाने चाहिए, ताकि यह किसी के लिए हानिकारक न हो। उपलब्ध संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए ताकि ऐसे परिणाम प्राप्त हों जो उनके समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करें। प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों को बनाए रखने के लिए कानूनी ढांचे को निष्पक्ष तरीके से लागू किया जाना चाहिए। समाज के लोगों को वैध संगठनों या प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी राय व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए। इसमें कमजोर और पिछड़े समूह भी शामिल हैं। सुशासन प्रथाएँ जनता के हितों को बनाए रखने में मदद करती हैं। सुशासन किसी संगठन को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए मौजूदा संसाधनों का इष्टतम और कुशल उपयोग करने में सक्षम बनाता है। सुशासन प्रथाएँ शक्ति और पद के अत्यधिक उपयोग के विरुद्ध जाँच और संतुलन भी सुनिश्चित करती हैं।

शासन प्रक्रिया में जनता की भागीदारी तभी प्राप्त की जा सकती है जब सुशासन प्रथाओं को लागू किया जाए। सुशासन दिवस विभिन्न पहलों के माध्यम से नैतिक शासन, पारदर्शिता और नागरिक भागीदारी पर ज़ोर देता है। इन पहलों का उद्देश्य प्रशासन को अधिक कुशल, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित बनाना है। ई-गवर्नेंस, डिजिटल साक्षरता और सरकारी सेवाओं तक निर्बाध पहुँच को बढ़ावा देता है। नागरिकों को सार्वजनिक सूचना तक पहुँचने के लिए सशक्त बनाकर पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। सरकारी परियोजनाओं पर प्रतिक्रिया प्रदान करके नीति निर्माण में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। पूरे भारत में स्वच्छता, सफ़ाई और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है। लाभार्थियों को सीधे सब्सिडी हस्तांतरित करता है, भ्रष्टाचार को कम करता है और लक्षित वितरण सुनिश्चित करता है। कुशल शासन के लिए देरी को सम्बोधित करते हुए सरकारी परियोजनाओं के समय पर निष्पादन की निगरानी करता है।

"बांग्लादेश के कुत्सित प्रयास, अनर्गल और तथ्यविहीन आरोप।"

यह बहुत ही दुखद है कि पड़ोसी बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार (हिंसा, मारपीट, अत्याचार) किया जा रहा है और वहां हिंदू धार्मिक स्थलों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। मंदिरों में तोड़फोड़, आगजनी, पुजारियों के साथ मार-पीट की घटनाएं साबित करतीं हैं कि बांग्लादेश में आज हिंदू सुरक्षित नहीं हैं। पाठकों को जानकारी के लिए बताता चलूं कि कुछ समय पहले राज्यसभा में बांग्लादेश के संदर्भ में प्रस्तुत आंकड़ों में यह बताया गया था कि बांग्लादेश में इस साल आठ दिसंबर तक हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के 2,200 मामले सामने आए हैं। वास्तव में यह दर्शाता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। न केवल बांग्लादेश बल्कि पाकिस्तान में भी आज हिंदू सुरक्षित नहीं हैं। आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान में इस साल अक्टूबर तक हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के 112 मामले सामने आए। वहीं, पिछले साल बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 302 घटनाएं सामने आई थीं, जबकि पाकिस्तान में वर्ष 2023 में इस तरह की 103 घटनाएं हुई थीं। बहरहाल, बांग्लादेश में मैमन सिंह और दिनाजपुर जिलों में 8 देव मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। बांग्लादेश में आज हिंसा इस कदर बढ़ गई है कि हिन्दूओं के श्मशान घाट तक भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। नाटोर के काशिमपुर सेंट्रल श्मशान घाट स्थित मंदिर के पुजारी की नृशंस हत्या और मंदिर में लूटपाट की घटना को वहां की पुलिस ने डकैती की वारदात बता दिया, आखिर इससे बड़ी बात और भला क्या हो सकती है ? आज बांग्लादेश में कट्टरपंथ अपने चरम पर है और कहना ग़लत नहीं होगा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं कर पा रही है। वास्तव में, सच तो यह है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से ही निरंतर यातनाओं, अत्याचार और हिंसा का सामना करना पड़ रहा है।अंतरिम सरकार न केवल अपनी जिम्मेदारी निभा पा रही है, बल्कि भारत पर अनर्गल और आधारहीन आरोप तक लगाए जा रहे हैं। यह विडंबना ही है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की मीडिया शाखा ने हाल ही की घटना के संदर्भ में यह कहा है कि हाल ही में मारा गया शख्स हिंदू पुजारी नहीं था और उसकी मौत सांप्रदायिक हिंसा से नहीं बल्कि श्मशान घाट में चोरी से जुड़ी थी। सरकार ने हिंदू समुदाय के एक शख्स की हत्या के संबंध में इस्कॉन कोलकाता द्वारा किए गए दावों को खारिज कर दिया। अंतरिम सरकार द्वारा गठित एक जांच आयोग ने कहा है कि उसने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के शासन के दौरान कथित रूप से 'जबरन गायब' करने की घटनाओं में भारत की 'संलिप्तता' पाई है। आयोग का अनुमान है कि जबरन गायब किए गए लोगों की संख्या तीन हजार से ज्यादा हो सकती है। सच तो यह है कि आयोग ऐसा कहकर भारत को कटघरे में खड़ा करने का कुत्सित प्रयास कर रहा है। आयोग का यह कहना कि कुछ बांग्लादेशी कैदी अब भी भारतीय जेलों में हो सकते हैं, दर्शाता है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत पर अनर्गल, तथ्यविहीन आरोप लगाकर भारत को एक प्रकार से अनदेखा कर रही है और भारत की छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खराब करने का कुत्सित व गंदा प्रयास कर रही है। कहना ग़लत नहीं होगा कि हाल फिलहाल के दिनों में भारत-बांग्लादेश के बीच जो भी हो रहा है,प्रभाव दोनों देशों की सीमा से सटे इलाकों पर साफ देखा जा सकता है। यह कटु सत्य है कि बांग्लादेश में शेख़ हसीना सरकार के जाने और अंतरिम सरकार के आने के बाद से ही भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध तनाव के दौर से गुज़र रहे हैं। बांग्लादेश की ऐसी हरकतों से दोनों पड़ोसी देशों के बीच अविश्वास की खाई निश्चित ही और अधिक चौड़ी होगी और बांग्लादेश के आधारहीन दावों के दूरगामी परिणाम होंगे, जिसका दोनों देशों के आपसी व्यापार, आवाजाही और सामाजिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक रिश्तों पर गहरा और व्यापक असर पड़ेगा।

सुनील कुमार महला, स्वतंत्र टिप्पणीकार, उत्तराखंड।

अटल जी सकारात्मक ऊर्जा के प्रेरणास्रोत थे

प्रेषक स्वतंत्र लेखक
हरिहर सिंह चौहान इन्दौर

'जो भारत को वैश्विक शक्ति देकर गया, हर एक क्षेत्र में शक्तिशाली व ठोसपन रखने वाले भारतीय जनतंत्र और जनमानस के हमदर्द युगक्षेष्ठ राष्ट्र सेवक भारत रत्न स्व अटल बिहारी वाजपेई जी ही थे। जिन्होंने भारत को उच्चाइयों पर ले जाने हेतु समय रहते पारमाणु शक्ति की धाक पूरी दुनिया में जमाईं। विश्व के सिरमौर देशों ने भी इस शांतिदूत अहिंसात्मक भारत की ताकत को पहचान लिया था। आज तभी तो हमारा देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। यह उन्हीं दूरदर्शी सोच के कारण सब सम्भव हो पाया। अटल जी जो सदैव अटल ही थें उन्होंने भारत के भाल को बढ़या था। हमारे देश के वह सही में एक रत्न ही थें तभी तो साहित्यकार जनसेवक राष्ट्रभाषा हिन्दी के सेवक और राष्ट्रभक्त भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई जी को आज भी पूरी दुनिया याद करतीं हैं। मस्तमौला अल्हड़पन बेबाक तरीके से जीवन में आंनद लेने वाले मस्ती में जीवन जीने वाले उन्हीं अटल जी की आज जन्मजयंती दिवस पर फिर ग्वालियर याद आता है। जहां उन्होंने अपनी मातृभूमि को जाना और फिर स्वदेश की आन बान शान के लिए लखनऊ चलें गये। उत्तरप्रदेश तो हमेशा से वीरों देशभक्तों की कर्मभूमि रही है। जहां तप के हीरा बनने के लिए वह आजादी की लड़ाई में गांधी जी वह अन्य आजादी के दिवानो के तराने सुन सुन कर वह बड़े हुए। तभी तो देशप्रेम उनके मन-मस्तिष्क पर हिलौरें लेता था। इसी लिए वह कलमकार बन काव्य रचनों में अपनी बात रखने लगे। अपनी अभिव्यक्ति को जग में फैलने का फैसला लेते हुए उन्होंने पाञ्चजन्य का शंखनाद करते हुए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखा में जाने लगे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ने लगे राष्ट्र सेवा हेतु उनका मन राजनीति में लें आया। राजनीति के आजातशत्रु बन उन्होंने भारत को उच्चाइयों पर पहुंचाया। देश की युवा तरुणाई को जागने के लिए हिन्दी भाषा को विश्व पटल पर पहुंचने के लिए वह लिखते रहे। अपनी कविता के मध्यम से उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, हार नहीं मानूंगा....या फिर काल के कापल से लिखता हूं लिखता चला जाता हूं। मौत से ठन गई जैसी कालजई रचनाएं हैं जो उन्होंने जीवन का सब कुछ उसी में समर्पित कर दिया। वह तभी तो हिन्दी भाषा के पक्षधर थे जब भी हिन्दी भाषा की बात होगी तो अटल जी को भी याद किया जाता रहेगा क्योंकि उस जमाने में विश्व चौधरी देशों में हिन्दी भाषा में भाषण उन्होंने ही दिया था। उनके काव्य मन में देश पहले आ रहा है तभी वह राजनीति में जनसेवा में समाज के कमजोरो की आवाज बन वह संसद में पहुंच गए। विपक्ष की कड़ी में वह शुरुआत में धीरे धीरे जनमानस के बीच पहुंच कर अपनी दबी आवाज को उठाने में अपने धारदार भाषणों में नपे-तुले शब्दों के साथ काव्य धारा का प्रभाव भी उनके भाषणों में रहती थी। संसद में कम सदस्य से वह डरें नहीं बल्कि वह आगे बढ़े। तभी तो उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अटल जी को अपने प्रतिनिधिमंडल में उन्हें विदेश भेजा था। सत्ता पक्ष व विपक्ष के इस तालमेल से सबक सभी को लेना चाहिए। जब वह देश के प्रधानमंत्री बने तो विपक्ष को कभी भी नजर अंदाज नहीं किया वह समझोता एक्सप्रेस भारत पाक बस सेवा आदि ऐसे शन्ति व भाईचारे को बढ़ाने के कार्य किए। पर जहां शक्ति की व कठोर बनाने की बात आई तो वह कहने लगे हार नहीं मानूंगा। अटल जी सकारात्मक ऊर्जा के प्रेरणास्रोत थें जिन्होंने हमेशा भारत के स्वाभिमान को बढ़ाने का प्रयत्न ही किया। कर्मनिष्ठ कर्मयोगी अटल जी कठिन से कठिन समय में भारत के गौरव को कम नहीं होने दिया। यही उनकी कार्यक्षमता व कार्यकुशलता थी। उन्हें भारत कभी भी नहीं भूला पायेगा आज 25 दिसंबर उनकी जन्मजयंती पर उन्हें शत शत नमन।

"मजबूत होते भारत-कुवैत द्विपक्षीय संबंध"

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ऐतिहासिक कुवैत यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूती मिली है।चार दशक से अधिक समय में इस खाड़ी देश (कुवैत) की यात्रा करने वाले नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वर्ष 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद यह यात्रा 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली कुवैत यात्रा थी। पाठकों को बताता चलूं कि भारत और कुवैत के संबंध हमेशा से ही मैत्रीपूर्ण रहे हैं और वर्ष 1961 में जब कुवैत अंग्रेजी शासन से आजाद हुआ, तब भारत उसके साथ संबंध बनाने वाले शुरुआती देशों में शामिल था। कहना ग़लत नहीं होगा कि लंबे समय बाद भारत के प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा से भारत का पश्चिमी एशियाई जुड़ाव और अधिक सुनिश्चित तथा मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी और कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल-अहमद अल-जाबेर अल- सबा की बातचीत से यह उजागर हुआ है कि भारत और कुवैत कूटनीतिक और आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार हैं। इस यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री मोदी को कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ मुबारक अल-कबीर' से सम्मानित किया जाना दोनों देशों के पारस्परिक सम्मान का सूचक है। वास्तव में यह कदम दोनों देशों के रिश्तों की गहराई और महत्व को दर्शाता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, परस्पर सौहार्द और सहयोग की भावना इनके बीच गहरी रणनीतिक साझीदारी का रास्ता खोलते हैं। कहना ग़लत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कुवैत यात्रा आर्थिक संबंधों के साथ ही सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण रही। वास्तव में, अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने ऐसे अनेक लोगों से मुलाकात की जिन्होंने भारत-कुवैत संबंधों को मजबूत करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पाठकों को बताता चलूं कि इनमें अब्दुल्ला अल-बारून भी शामिल हैं, जिन्होंने एक अनुवादक के रूप में भारतीय महाकाव्यों 'रामायण' एवं 'महाभारत' का अरबीभाषियों के लिए अनुवाद किया है। सच तो यह है कि भारत के प्रधानमंत्री की हालिया कुवैत यात्रा ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग की शुरुआत की है। इस दौरान दोनों देशों के बीच हुए समझौते और रणनीतिक सहमतियां पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिहाज से भी अहम हैं। महत्वपूर्ण है कि कुवैत यात्रा के दौरान भारत और कुवैत के बीच रक्षा, खेल, संस्कृति और सौर क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, जो दोनों देशों के बीच संबंधों को निश्चित ही और अधिक मजबूती और प्रगाढ़ता प्रदान करेंगे। गौरतलब है कि कुवैत भारत का प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता रहा है और आज भी है। आंकड़े बताते हैं कि कुवैत, भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है, जो देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को तीन प्रतिशत तक पूरा करता है।

यहां यह कहना ग़लत नहीं होगा कि इससे यह आपूर्ति सुरक्षित होने के साथ ही खाड़ी क्षेत्र में भारत की समग्र ऊर्जा सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही साथ, कुवैत के साथ रक्षा सहयोग भारत की 'ऐक्ट बेस्ट नीति' को भी निश्चित ही मजबूती प्रदान करेगा। आज कुवैत में बहुत से भारतीय निवास करते हैं और वहां की सामाजिक संरचना में भारतीयों का स्थान प्रवासियों के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीयों ने कुवैत को इंजीनियरिंग व शिक्षा, मेडिकल समेत अनेक क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण और अहम्-योगदान दिया है।कुवैत भी बरसों-बरसों से भारत का एक महत्वपूर्ण ऊर्जा सप्लायर रहा है, जबकि अनेक भारतीय विशेषज्ञ और भारतीय श्रमशक्ति कुवैत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसी बीच, कुछ समय पहले ही कुवैत नेशनल रेडियो द्वारा साप्ताहिक हिंदी रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत किया जाना

निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि कुवैत के लिए प्रवासी भारतीय कितने महत्वपूर्ण और अहम्-हैं। इतना ही नहीं, गत जून में कुवैत की एक इमारत में आग लगने से हुई भारतीयों की मौतों के बाद कुवैत ने जिस तरह का सहयोग दिया, वह भी दोनों देशों के मजबूत संबंधों को ही दर्शाता है। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने प्रवासियों को बेहतर वाणिज्यिक सेवाओं और श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा का सकारात्मक व ठोस आश्वासन दिया है, जो विदेशों में अपने नागरिकों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निश्चित ही इससे कुवैत में प्रवासी भारतीयों के आत्मविश्वास में बढ़ोत्तरी होगी। यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि पीएम मोदी की इस ऐतिहासिक दो दिवसीय कुवैत यात्रा के दौरान भारत और कुवैत ने संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' तक बढ़ाने पर सहमति जताई है और रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को नियमित बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह और भी अधिक महत्वपूर्ण है कि ऊर्जा सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से दोनों पक्षों ने इस बात पर जोर दिया है कि वे अपने-अपने देशों की कंपनियों को तेल और गैस के अन्वेषण तथा उत्पादन, रिफाइनिंग, इंजीनियरिंग सेवाओं, और 'पेट्रोकेमिकल' उद्योगों में सहयोग बढ़ाने के लिए समर्थन प्रदान करेंगे।अंत में, यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा ने निस्संदेह कुवैत व भारत के संबंधों को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया है।उनकी यह यात्रा निश्चित ही खाड़ी क्षेत्र में एक जिम्मेदार साझेदार के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करेगी। सच तो यह है कि भारतीय प्रधानमंत्री का कुवैत दौरा भारत और खाड़ी देशों के बीच बढ़ते संबंधों की यात्रा में एक अहम मील का पत्थर साबित होगा। यह दौरा कूटनीति, व्यापार और समुदाय संवाद की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है जो भारत और कुवैत के द्विपक्षीय रिश्तों को जहां एक ओर मजबूती प्रदान करेगा वहीं दूसरी ओर यह दोनों देशों के बीच भविष्य में सहयोग की रूपरेखा भी तय करेगा।

सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर, कालमिस्ट व युवा साहित्यकार, उत्तराखंड।

आयुष्मान भारत से कैंसर का समय पर शुरू होने लगा इलाज, कैसे उठा सकते हैं योजना का लाभ?

परिवहन विशेष न्यूज

द लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथईस्ट एशिया में छपी रिसर्च से पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों में कैंसर का इलाज शुरू करने में कम समय लगने लगा है। इसमें उन लोगों की संख्या उल्लेखनीय रूप से अधिक है जिनका इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत चल रहा है। कम आमदनी वाले लोगों की तुलना में उच्च आय वाले लोग समय पर इलाज शुरू करवा देते हैं।

नई दिल्ली। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के तहत रजिस्ट्रेशन से देश में कैंसर का उपचार अब समय पर शुरू होने लगा है। जांच के बाद जल्द इलाज शुरू होने के मामलों में 33 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। 2018 में यह योजना शुरू होने के बाद से 30 दिनों के भीतर उपचार शुरू होने की संभावना 1995 और 2017 के बीच इलाज कराने वाले रोगियों की तुलना में 36 प्रतिशत अधिक हो गई है।

'द लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथईस्ट एशिया' में प्रकाशित निष्कर्षों से पता चला कि पीएम-जेएवाई लागू होने के बाद अब ज्यादा लोग कैंसर का समय पर उपचार शुरू कराने लगे हैं। अनुसंधानकर्ताओं में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआइएमईआर), चंडीगढ़ के शोधकर्ता भी शामिल थे।

अब जल्दी शुरू हो रहा कैंसर का इलाज

अनुसंधानकर्ताओं ने तमिलनाडु, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे छह राज्यों के सात प्रमुख कैंसर अस्पतालों में अक्टूबर 2020 और मार्च 2022 के बीच भर्ती किए गए लगभग 6,700 कैंसर रोगियों का विश्लेषण किया। स्वास्थ्य देखभाल लागत और जीवन की गुणवत्ता सहित कई पहलुओं पर मरीजों से बात की गई।

इसमें पाया गया कि जांच के उपरांत रोग का पता चलने के बाद कैंसर का उपचार शुरू करने की सामान्य अवधि 20 दिन है। सिर और गर्दन के कैंसर वाले मरीजों में इलाज शुरू करने की अवधि सबसे अधिक 29 दिन है। स्तन कैंसर के मरीजों का 25 दिन में और ब्लड कैंसर के मरीजों का सबसे कम 11 दिन में इलाज शुरू हो जाता है।

आयुष्मान भारत योजना से हो रहा फायदा

अध्ययन में कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में कैंसर का इलाज शुरू करने में कम समय लगने लगा है। इसमें उन लोगों की संख्या उल्लेखनीय रूप से अधिक है, जिनका इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत चल रहा है। आयुष्मान भारत में रजिस्ट्रेशन के बाद कैंसर रोगियों का समय पर उपचार शुरू होने की संभावना बढ़ गई है। कम आमदनी वाले लोगों की तुलना में उच्च आय वाले लोग समय पर उपचार शुरू करने में देरी नहीं करते।

आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस

जन आरोग्य योजना की अधिकारिक वेबसाइट (https://beneficiary.nha.gov.in/) पर जाएं।

यहां आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक अकाउंट जैसे जानकारियां दर्ज करें।

यहां आपको स्क्रीन पर अपनी और अपने परिवार की डिटेल शो होगी।

अप्लाई ऑप्शन सेलेक्ट करें, न्यू पेज ओपन होगा जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म होगा।

आवेदन फॉर्म को भरने के हाद आपको डॉक्युमेंट्स अपलोड करना होगा।

डॉक्युमेंट अपलोड करने के बाद आपको ओटीपी वैलिडेशन करना होगा।

आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, जिससे आप प्रोसेस को ट्रैक कर सकते हैं।

"भारत के भविष्य के निर्माण में नवाचार और आत्मनिर्भरता का मार्ग"

परिवहन विशेष न्यूज

"इंडिया एट 2047 : भविष्य के भारत का सपना साकार करें"
"हरित और डिजिटल भारत की ओर तेजी से बढ़ता कदम"
"इंडिया एट 2047" सम्मेलन : भविष्य का भारत

21 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली के प्रतिष्ठित एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, स्टार्टअप और उद्यमी संघ (IBSEA) द्वारा ₹इंडिया एट 2047₹ सम्मेलन और भारत के महारथी सम्मान 3.0 का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 2047 तक भारत को एक विकसित, आत्मनिर्भर और विश्व स्तरीय राष्ट्र के रूप में देखना था। सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों, उद्यमियों, शिक्षाविदों और समाजसेवियों ने भाग लिया और देश के विकास के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया। इस सम्मेलन के माध्यम से भारत के भविष्य को नई दिशा देने और युवा पीढ़ी को अपने सपनों का भारत बनाने के लिए एक साझा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया।

सम्मेलन का उद्घाटन वैदिक मंगलाचरण, दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुआ। इसमें देश की संस्कृति और परंपराओं को समर्पित करते हुए ज्योर्तिवेद विज्ञान संस्थान वैदिक मंगलाचरण डॉ राघव नाथ झा ने आध्यात्मिक वातावरण तैयार किया गया। साथ ही, गणेश वंदना सुरम्या इंस्टीट्यूट की छात्राओं द्वारा की गई। इस अवसर पर आईबीएसईए के अध्यक्ष डॉ. अंशुमान सिंह, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री इकबाल सिंह लालपुरा, विश्व शांति दूत जैन लोकेश मुनि, और अन्य सम्मानित अतिथियों ने राष्ट्र निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार साझा किए।

विविध सत्रों और पैनल चर्चाओं में विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा हुई। हरित ऊर्जा, डिजिटल परिवर्तन, महिला सशक्तिकरण, स्टार्टअप नवाचार, कृषि विकास और शिक्षा के क्षेत्र में भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। यह सम्मेलन न केवल व्यापार और नवाचार के लिए एक मंच था, बल्कि देश के सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया था।

मुख्य विषय: "इंडिया एट 2047"

सम्मेलन का मुख्य विषय था – 2047 तक भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाना। इस विषय के अंतर्गत विभिन्न सत्र आयोजित किए गए, जिनमें कृषि, शिक्षा, तकनीकी विकास, पर्यावरण संरक्षण और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजने पर चर्चा हुई। इन सत्रों में नीति निर्माताओं, उद्योगपतियों और समाजसेवियों ने भारत को भविष्य में सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए साझा दृष्टिकोण तैयार किया।

विविध सत्र और विषयगत चर्चाएं:

सम्मेलन में विभिन्न सत्रों का आयोजन किया गया, जिनमें ₹हरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हुए₹, ₹डिजिटल इंडिया और तकनीकी नवाचार₹, ₹महिला नेतृत्व और उद्यमिता₹, ₹खेती और ग्रामीण विकास₹, ₹शिक्षा क्षेत्र में सुधार₹, और ₹समाज में सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण₹ जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल थे। इन सत्रों में वक्ताओं ने अपनी विशेषज्ञता और अनुभव साझा करते हुए भारत के भविष्य के लिए एक नई दृष्टि प्रस्तुत की।

हरित ऊर्जा पर चर्चा करते हुए,

विभिन्न विशेषज्ञों ने ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और अक्षय ऊर्जा स्रोतों के विस्तार के उपायों पर जोर दिया। डिजिटल इंडिया की दिशा में, कई स्टार्टअप ने अपने अभिनव समाधान प्रस्तुत किए और निवेशकों ने इनकी आर्थिक सहायता की। महिला सशक्तिकरण पर विशेष चर्चा की गई, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

स्टार्टअप इन्वेस्टर मीट:

सम्मेलन का एक प्रमुख आकर्षण स्टार्टअप इन्वेस्टर मीट था, जिसमें युवा उद्यमियों ने अपने व्यवसायिक विचार प्रस्तुत किए। इन स्टार्टअप्स को अवसर प्रदान किए गए, जिससे वे अपने उद्यमशीलता की संभावनाओं को नया आयाम दे सकें। निवेशकों ने स्टार्टअप्स को विभिन्न वित्तीय सहायता प्रदान की, जिससे उनके नवाचार और विस्तार को गति मिली।

सम्मानित व्यक्तित्व और पुरस्कार:

सम्मेलन के अंतिम चरण में विभिन्न क्षेत्रों में समाज की सेवा करने वाले 50 विशिष्ट व्यक्तियों को ₹भारत के महारथी सम्मान 3.0₹ से सम्मानित किया गया। इसमें डॉ. सीमा अग्रवाल को सर्वश्रेष्ठ महिला प्रेरक, अमित वर्मा को श्रेष्ठ ऊर्जा वैज्ञानिक, अनुजा मेहता को स्वच्छता क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इन सभी व्यक्तियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दिया है और समाज के समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भविष्य की योजनाएं और सामाजिक परिवर्तन:

IBSEA ने आगामी वर्षों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं प्रस्तुत कीं, जिनमें विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर ध्यान देने वाले कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इनमें वोकल फॉर लोकल, महिला नेतृत्व, डिजिटल इंडिया और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल शामिल हैं। ये कार्यक्रम भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

समापन सत्र में, राष्ट्रगान के साथ सम्मेलन का समापन हुआ। सभी प्रतिभागियों ने एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया। डॉ. अंशुमान सिंह ने कहा, "हमारा लक्ष्य है कि हर भारतीय अपनी क्षमताओं को पहचान कर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करे। 'इंडिया एट 2047' हमारे सपनों के भारत को साकार करने का एक महत्वपूर्ण कदम है।"

इस भव्य आयोजन ने भारत के भविष्य की दिशा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास किया है। इस प्रकार के सम्मेलन से देश के विकास में नवाचार, तकनीकी उत्कृष्टता और समाज में सकारात्मक परिवर्तन को बढ़ावा मिलेगा।

संपर्क जानकारी
अध्यक्ष: डॉ. अंशुमान सिंह

2024 में म्यूचुअल फंड ने तोड़े निवेश के सारे रिकॉर्ड, 17 लाख करोड़ रुपये बढ़ा AUM

परिवहन विशेष न्यूज

म्यूचुअल फंड ने साल 2024 में काफी उम्दा प्रदर्शन किया। उसकी असेट अंडर मैनेजमेंट में 17 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। म्यूचुअल फंड की ग्रोथ तेजी से बढ़ते शेयर बाजार मजबूत आर्थिक वृद्धि और निवेशकों की बढ़ती भागीदारी से प्रेरित रही। इंडस्ट्री की असेट अंडर मैनेजमेंट नवंबर के अंत तक 68 लाख करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गई।

नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड उद्योग ने 2023 में शानदार प्रदर्शन के बाद 2024 में अपनी ग्रोथ की रफ्तार को बनाए रखा। उनकी असेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) में 17 लाख करोड़ रुपये की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की। म्यूचुअल फंड में तेजी से बढ़ते शेयर बाजार, मजबूत आर्थिक वृद्धि और निवेशकों की बढ़ती भागीदारी से प्रेरित रहा।

विशेषज्ञों का अनुमान है कि इंडस्ट्री में सकारात्मक रुझान 2025 में भी जारी रहेगा। म्यूचुअल फंड उद्योग संघ (एम्फी) के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 में 9.14 लाख करोड़ रुपये का पर्याप्त शुद्ध प्रवाह देखा गया, साथ ही निवेशकों की संख्या में 5.6 करोड़ की उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

2025 में म्यूचुअल फंड उद्योग की परिसंपत्तियों में स्वस्थ गति से वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है। खुदरा निवेशकों के बीच बढ़ती पहुंच के साथ, इक्विटी फंड में प्रवाह, विशेष रूप से व्यवस्थित निवेश योजनाओं

(एसआईपी) के माध्यम से मजबूत रहने की संभावना है।

कौस्तुभ बेलापुरकर, निदेशक-प्रबंधक रिसर्च, मॉर्निंगस्टार इन्वेस्टमेंट रिसर्च इंडिया

SIP की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसने अकेले 2.4 लाख करोड़ रुपये का योगदान दिया। इस निवेश से उद्योग की एयूएम बढ़कर नवंबर के अंत तक 68 लाख करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गईं, जो 2023 के अंत में दर्ज 50.78 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 33 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

यह बदलाव भारतीय अर्थव्यवस्था के विस्तार और खुदरा निवेशकों के बीच बढ़ती वित्तीय जागरूकता से समर्थित है, जो कम लागत और अधिक सुविधा के साथ उच्च 'रिटर्न' की तलाश में हैं।

गणेश मोहन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बजाज फिनसर्व एएमसी

यह वृद्धि 2023 में एयूएम में 27 प्रतिशत और 11 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ-साथ पिछले वर्षों में हुई वृद्धि से कहीं अधिक थी। 2022 में उद्योग में सात प्रतिशत की वृद्धि और एयूएम में 2.65 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। वहीं 2021 में लगभग 22 प्रतिशत की वृद्धि और परिसंपत्ति आधार में लगभग सात लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। पिछले चार वर्षों में, इंडस्ट्री ने सामूहिक रूप से अपने एयूएम में 30 लाख करोड़ रुपये की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है।

जनवरी 2025 का ये खास डेटा तय करेगा, ब्याज दरों में कटौती होगी या फिर नहीं

आरबीआई ने लगभग दो साल तक प्रमुख नीतिगत दर रेपो में कोई बदलाव नहीं किया। उन्होंने आर्थिक विकास पर महंगाई घटाने को तरजीह दी। मौजूदा वित्त वर्ष की सितंबर में जीडीपी ग्रोथ 7 तिमाहियों के निचले स्तर पर आ गई थी। ICICI बैंक की एक रिपोर्ट का कहना है कि अगर खाने-पीनों की चीजों का दाम घटता है तो रेपो रेट में ढील देने का पक्ष मजबूत होगा।

नई दिल्ली। अगर जनवरी में खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट आती है तो आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) फरवरी में रेपो रेट में कटौती पर विचार कर सकती है। ICICI बैंक की एक रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि खाद्य कीमतों में गिरावट रेपो रेट में ढील देने का पक्ष मजबूत होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई केंद्रीय मंत्री पहले ही आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए ब्याज दरों में कटौती की वकालत कर चुके हैं।

पिछली एमपीसी मीटिंग दिसंबर 2024 की शुरुआत में हुई। यह पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुआई वाली कमेटी की आखिरी मीटिंग थी। इस एमपीसी की बैठक के मिनट्स से रेपो रेट को लेकर सदस्यों के नरम रुख का पता चला है। दो सदस्यों ने दरों में कटौती की वकालत की थी।

हालांकि ब्याज दरों को मौजूदा स्तर पर ही बनाए रखने के पक्ष में रहने वाले सदस्यों ने कहा था कि अभी दरों में कटौती का समय उचित नहीं है। उन्होंने संकेत दिया था कि आने वाले महीनों में कम खाद्य मुद्रास्फीति इस तरह के कदम के लिए सही अवसर दे सकती है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, नवंबर में खुदरा मुद्रास्फीति 5.48 प्रतिशत रही, जबकि अक्टूबर में यह 6.21 प्रतिशत थी। आरबीआई ने दो प्रतिशत की घट-बढ़ के साथ मुद्रास्फीति को चार प्रतिशत रखने का लक्ष्य रखा है।

ब्याज दर ऊंची होने से भारी नुकसान

ICICI बैंक की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फेडरल ओपेन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) के आक्रामक रुख से प्रेरित होकर अमेरिकी डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ और भारतीय करेंसी दबाव में रही। रुपये में गिरावट के चलते विदेशी निवेशकों ने 0.2 अरब डॉलर का अपना निवेश भारतीय बाजार निकाल लिया।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बिगड़ते आर्थिक दृष्टिकोण से निकट भविष्य में भारतीय मुद्रा के दबाव में रहने की आशंका है। रिपोर्ट में घरेलू मुद्रास्फीति के रुझान और बाहरी कारकों के बीच परस्पर क्रिया पर प्रकाश डाला गया है, जो आने वाले महीनों में आरबीआई के मौद्रिक नीति के फैसलों को आकार देगा।

क्या नए आरबीआई गवर्नर घटाएंगे ब्याज दर

पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुआई में आरबीआई ने लगभग दो साल तक प्रमुख नीतिगत दर रेपो में कोई बदलाव नहीं किया। उन्होंने आर्थिक विकास पर महंगाई घटाने को तरजीह दी। मौजूदा वित्त वर्ष की सितंबर में जीडीपी ग्रोथ 7 तिमाहियों के निचले स्तर पर आ गई थी।

अब नजरें नए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा पर है, जो फरवरी 2025 में पहली पहली बार एमपीसी मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। अगर नवंबर की तरह दिसंबर और जनवरी में भी महंगाई काबू में रही, तो आरबीआई फरवरी में रेट कट कर सकता है।

AI, EV और ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए खास रियायत की मांग, क्या सरकार सुनेगी गुहार?

परिवहन विशेष न्यूज

उद्योग संगठन सीआईआई का कहना है कि जीडीपी विकास में कृषि की हिस्सेदारी 14 प्रतिशत है जबकि प्राथमिक सेक्टर के कर्ज का 18 प्रतिशत कृषि को दिया जाता है। यह हिस्सेदारी तब निर्धारित हुई थी जब जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत थी। उद्योग संगठन की मांग है कि कर्ज से जुड़े प्राथमिक सेक्टर के नियमों में बदलाव जरूरी है और सरकार कमेटी का भी गठन कर सकती है।

नई दिल्ली। औद्योगिक संगठनों ने आगामी बजट में बैंकों से मिलने वाले कर्ज से जुड़े प्राथमिक सेक्टर की सूची में इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी), डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसे उभरते सेक्टरों को शामिल करने की मांग की है। अभी कर्ज से जुड़े प्राथमिक सेक्टर में कृषि, शिक्षा, एमएसएमई मुख्य रूप से शामिल है। उद्योग संगठन सीआईआई का कहना है कि जीडीपी विकास में कृषि की हिस्सेदारी 14 प्रतिशत है, जबकि प्राथमिक सेक्टर के कर्ज का 18 प्रतिशत कृषि को दिया जाता है। यह हिस्सेदारी तब निर्धारित हुई थी, जब जीडीपी विकास में कृषि की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत थी। उद्योग जगत का मानना है कि एआई, ग्रीन एनर्जी, ईवी जैसे सेक्टर दुनिया भर में तेजी से उभर रहे हैं और इस सेक्टर पर विशेष ध्यान नहीं देने पर भारत इनमें पिछड़ सकता है।

इससे इन उत्पादों के लिए आयात पर निर्भरता

बढ़ेगी। एआई, ग्रीन एनर्जी, ईवी जैसे सेक्टर की अनदेखी भी नहीं की जा सकती है क्योंकि ये कार्बन उत्सर्जन से जुड़े हुए हैं। भारत भी कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की प्रतिबद्धता से जुड़ा हुआ है। यह सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग पर आधारित है। यदि इन सेक्टर्स पर विशेष ध्यान दिया जाता है तो बड़ी संख्या में रोजगार का भी सृजन होगा। उद्योग संगठन का कहना है कि कर्ज से जुड़े प्राथमिक सेक्टर के नियमों में बदलाव जरूरी है और सरकार चाहे तो एक कमेटी का भी गठन कर सकती है। उद्यमियों का कहना है कि बजट में इलेक्ट्रिक कार की खरीदारी के लिए बैंकों से मिलने वाले लोन में सरकार की तरफ से विशेष रियायत मिलनी चाहिए। इसका कारण यह है कि इलेक्ट्रिक कार की खरीदारी पर इलेक्ट्रिक दोपहिया की तरह सरकार से कोई सब्सिडी भी नहीं दी जाती है।

अर्थशास्त्रियों से पीएम मोदी की मीटिंग

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजट को लेकर मंगलवार यानी आज अर्थविदों के साथ मीटिंग भी की। नीति आयोग के भवन में होने वाली बैठक में कुछ खास औद्योगिक सेक्टरों के विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया गया है। बैठक में कुछ केंद्रीय मंत्रियों और नीति आयोग के चेयरमैन सुमन बेरी भी शामिल हुए। बैठक के शुरुआत में नीति आयोग के चेयरमैन और वित्त सचिव देश की इकोनॉमी की दिशा व दशा पर दो अलग अलग नजरिया पेश किया।

दूसरी तिमाही में देश की आर्थिक विकास दर की रफ्तार सुस्त होने के बाद इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस तरह की बैठक सरकार हर आम बजट से पहले आयोजित करती है।

आयुष्मान भारत योजना और कैंसर

हाल ही में प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल 'द लांसेट' की एक स्टडी के अनुसार भारत में पिछले छह साल में कैंसर के समय पर इलाज में 36 प्रतिशत वृद्धि हुई है और इसका श्रेय आयुष्मान भारत पीएम-जन आरोग्य योजना को जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कहना ग़लत नहीं होगा कि आयुष्मान भारत योजना कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ने में एक बड़ी सीढ़ी साबित हुई है। उल्लेखनीय है कि केंद्र की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के तहत हर साल 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कराया जा सकता है, जिसमें पुरानी बीमारियां भी कवर होती हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी बीमा योजना है, जो गरीब और कमजोर परिवारों के लिए केंद्र सरकार द्वारा साल 2018 में शुरू की गई थी। गौरतलब है कि इस योजना के तहत, अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिनों और भर्ती के बाद के 15 दिनों तक के खर्च भी कवर किए जाते हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने इस योजना का विस्तार करते हुए 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को भी इसका पात्र बना दिया है। बहरहाल, पाठकों को बताता चलूं कि द लैंसेट रीजनल हेल्थ - साउथ ईस्ट एशिया में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 27 प्रमुख अस्पतालों में 6,695 कैंसर रोगियों के इलाज के इतिहास की जांच की, जिससे पता चला कि ज्यादातर मरीजों ने निदान के 20 दिनों के अंदर ही इलाज शुरू करवा लिया।अध्ययनकर्ताओं ने पाया कि 1995 से 2017 की अवधि की तुलना में 2018 से कैंसर के समय पर इलाज शुरू होने में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई।अध्ययन में दावा किया गया है कि एबी-पीएमजेएवाई योजना में रजिस्ट्रेशन न करवाने वालों के लिए समय पर इलाज की पहुंच में 30% सुधार हुआ, जबकि एबी-पीएमजेएवाई योजना का लाभ लेने वालों में 90% की वृद्धि हुई है. एबी-पीएमजेएवाई में कैंसर के इलाज के लिए 557 स्वास्थ्य लाभ पैकेज शामिल हैं। लैंसेट का यह कहना है कि इस योजना के आने से कैंसर के मरीजों का इलाज समय पर शुरू करने में मदद मिली है। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि कैंसर का पता चलने के एक महीने में अगर इलाज शुरू कर दिया जाए, तो कैंसर के खतरे की आशंका कम रह जाती है। यह अच्छी बात है कि केंद्र सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना से आम आदमी को भी अन्य बीमारियों के साथ ही कैंसर जैसी घातक व खतरनाक बीमारियों में भी समय पर उपचार मिल रहा है। यह काबिले-तारीफ है कि आयुष्मान भारत-पीएम जन आरोग्य योजना को लागू किये आज छह साल हो गये हैं और इसका लाभ लेने वाले रोगियों की सर्वाधिक संख्या के मामले में कैंसर चौथे नंबर पर है। केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के कारण अब गरीब तबके के लोग भी अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं और उन्हें समय पर इलाज मिल रहा है। यह अध्ययन रिपोर्ट बताती है कि कैंसर के इलाज में रेडियोथैरेपी के कारण सबसे अधिक देरी होती है। दरअसल, उच्च आय वाले देशों में प्रति ढाई लाख लोगों पर एक रेडिएशन थैरेपी यूनिट है और इस हिसाब से भारत में कुल 5,000 रेडिएशन थेरैपी यूनिट्स की जरूरत है, जबकि अभी इनकी संख्या 1,000 ही है। इसे देखते हुए रेडिएशन के क्षेत्र में विभिन्न ढांचागत सुविधाएं बढ़ाने की इस रिपोर्ट में सरकार से अपील की गई है। कुल मिलाकर, इस रिपोर्ट से यह पता चलता है कि केंद्र सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना से दूसरी बीमारियों के साथ कैंसर के क्षेत्र में भी समय पर उपचार मिल रहा है। बहरहाल, कहना ग़लत नहीं होगा कि आज भारत की आबादी विश्व में सर्वाधिक है और यहां चिकित्सकों की उपलब्धता और चिकित्सा सुविधाएं वैश्विक मानकों के अनुरूप नहीं है। हालांकि आज देश में अनेक मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, मेडिकल क्षेत्र में सीटें भी बढ़ाईं गईं हैं लेकिन

यूनेस्को का यह कहना है कि भारत के कई स्थानों पर एक हजार व्यक्तियों पर एक चिकित्सक भी उपलब्ध नहीं है।आज भी देश के विभिन्न ग्रामीण इलाकों के अस्पतालों अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता तो दूर सामान्य डॉक्टरों की मौजूदगी भी कम ही है। बावजूद इसके आयुष्मान योजना आज सरकार की एक बड़ी और नायाब पहल है। आज बहुत से लोग इस योजना का भरपूर फायदा उठा रहे हैं लेकिन आज भी जरूरत इस बात की है कि इस प्रकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई बाधा व दिक्कत पैदा न हो। भारत जैसे देश में सस्ती और सहज चिकित्सा सुविधाएं आज की जरूरत है। आज रूस ने कैंसर की वैक्सीन बना दी है, लेकिन सोचनीय बात यह है कि वैक्सीन बनाने में हमारा देश विश्व में सबसे आगे होने के बावजूद आज हमारा देश चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नई खोजों व अनुसंधानों में आखिर पीछे क्यों रह गया है ? बहरहाल, कहना ग़लत नहीं होगा कि कैंसर का इलाज खोजना चिकित्सा विज्ञान की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रहा है। इस गंभीर बीमारी से निपटने के लिए वैज्ञानिक दशकों से एक प्रभावी समाधान की तलाश कर रहे हैं। कहना ग़लत नहीं होगा कि आज भारत में भी कैंसर के इलाज के लिए वैक्सीन पर लगातार अनुसंधान व काम हो रहा है। सच तो यह है कि भारत के कई अनुसंधान संस्थान आज इस दिशा में प्रयासरत हैं, लेकिन इस दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। विश्व के अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में स्वास्थ्य बजट और अनुसंधान के लिए आवंटित राशि सीमित ही है।इस संबंध में यदि भारत अपने स्वास्थ्य बजट में वृद्धि करता है और अनुसंधान को प्राथमिकता देता है, तो वह कैंसर वैक्सीन खुद भी विकसित कर सकता है।

तेज रफ्तार का परिणाम, दोस्त का जन्मदिन बना दो युवकों का मृत्यु दिवस

सुनील बाजपेई

- जन्मदिन पार्टी के बाद तेज रफ्तार मोटर साइकिल से घर लौट रहे युवकों को मारी अज्ञात वाहन ने टक्कर

कानपुर। तेज रफ्तार वाहन लोगों की जान लेने में लगातार सफल हो रहे हैं। ऐसी ही एक घटना में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल से जा रहे युवकों की अज्ञात वाहन से टक्कर से मौत हो गई। दोनों अपने साथी की जन्मदिन पार्टी में शामिल होने के बाद घर वापस जा रहे थे।

मिली जानकारी के मुताबिक अचलगंज उन्नाव के गांव खन्नापुरवा निवासी सौरभ निषाद (20) गांव रहने वाले अपने दोस्त अंकित गौतम (19) के साथ बाइक पर कानपुर आया हुआ था।

पुलिस ने बताया कि रात लगभग पौने दो बजे दोनों बाइक से वापस उन्नाव लौट रहे थे। इसी दौरान गंगा पुल पर दोनों की मोटरसाइकिल की टक्कर एक अज्ञात वाहन से हो गई। जिसमें दोनों की मौके पर मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस को परिवार वालों ने बताया कि मृतक अंकित की आर वन 5 बाइक से दोनों युवक कानपुर में एक बर्थडे पार्टी में शामिल होने आए थे।

जानकारी के अनुसार अंकित अपने परिवार में सबसे छोटा था। पिता श्यामू के अलावा मां सीया देवी, बड़ा भाई आशीष और बहन ममता है।

पिता के मुताबिक सोमवार रात आठ बजे दोनों थोड़ी देर में आने की बात कहकर निकल गए थे। अंकित पिता के साथ खेती किसानी में मदद करता था। घटना के बाद दोनों युवकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर फरार वाहन चालक की तलाश कर रही है।

वरिष्ठ समाजसेवी मुशरफ खान की शहरवासियों से अपील - "थोड़ी सी सावधानी से हम दवाइयों के खर्च और नकली दवाइयों से बच सकते हैं"

आगरा, संजय साग़र सिंह। वरिष्ठ समाजसेवी मुशरफ खान ने कहा कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और अनियमित खानपान के कारण अधिकांश परिवारों में कोई न कोई बीमारी रहती है, जिससे दवाइयों का खर्च बढ़ता जा रहा है। इस बढ़ते खर्च का फायदा उठाकर नकली दवाइयों के कारोबारी जनता को धोखा दे रहे हैं। श्री खान साहब ने बताया कि थोड़ी सी सावधानी से हम दवाइयों के खर्च और नकली दवाइयों से बच सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि जब भी दवाइयाँ खरीदी जाएं, तो पक्का बिल अवश्य लें, क्योंकि नकली दवाइयों का कारोबार अक्सर बिना बिल के होता है। साथ ही, उन्होंने जेनरिक दवाइयों के उपयोग की सलाह दी, क्योंकि ये ब्रांडेड दवाइयों से सस्ती होती हैं, लेकिन उनका असर समान रहता है। उन्होंने आगे बताया कि जेनरिक दवाइयाँ जैसे सिपला, इंटास, मैनकाइंड आदि की कंपनियों से खरीदनी चाहिए। अंत में, श्री खान ने शहरवासियों को आगरा स्मार्ट सिटी के तहत स्थित स्मार्ट हेल्थ सेंटर की सुविधाओं का लाभ उठाने की अपील की, जहां नगर निगम क्लीनिक पर सस्ती दरों पर दवाइयाँ और पैथोलॉजी जांच उपलब्ध हैं। साथ ही दवाइयों पर 80% तक की छूट मिलती है और वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा परामर्श बहुत कम शुल्क में दिया जाता है।

हर भारतीय को क्रिसमस मनाने की बजाय अपने वीर शहजादों के बलिदान को सम्मान देना चाहिए : राजेश खुराना

आगरा, संजय साग़र सिंह। सामाजिक चिंतक राजेश खुराना ने शोक सप्ताह के दौरान गुरु गोविंद सिंह जी और उनके साहबजादों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि हर भारतीय को क्रिसमस मनाने की बजाय अपने वीर शहजादों के बलिदान को सम्मान देना चाहिए। उनका यह मानना है कि हमे बच्चों को हमारे वीर इतिहास और उनके बलिदानों के बारे में जागरूक करना चाहिए, ताकि वे समझ सकें कि धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए कितने महान पुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दी। श्री खुराना ने विशेष रूप से गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के शहीदी संघर्ष का उल्लेख किया, जहां पिता ने अपने छोटे पुत्रों को सत्य, धर्म और देश की रक्षा के लिए शहीद कर दिया, जो इतिहास में एक दुर्लभ उदाहरण है। उन्होंने आगे बताया कि 21 से 27 दिसंबर तक का सप्ताह सिख इतिहास में शोक का सप्ताह होता है, क्योंकि इस दौरान गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार ने संघर्ष किया और उनके दोनों छोटे पुत्र, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, सत्य और धर्म की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। अंत में श्री खुराना ने सवाल उठाया कि क्यों आज भारत में कुछ लोग क्रिसमस के जश्न में डूबे हुए हैं, जबकि हम अपने वीरों और उनके बलिदानों को भूलते जा रहे हैं। उनका यह संदेश था कि हमें अपने इतिहास को जानने और उसे याद रखने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने महान बलिदानियों की कुर्बानियों को सम्मान दे सकें और देशहित में, एक राष्ट्र के रूप में अपनी जड़ों से जुड़े रहें।

डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन उ.प्र. ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम विधायकों को सौंपा ज्ञापन

आगरा। डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन उ.प्र. के आव्हान पर संवर्ग की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम विधायकों को ज्ञापन सौंपा गया और उन्होंने आश्वस्त किया कि आपके मांग पत्र एवं ज्ञापन को पत्र के माध्यम से ससमय भेज दिया जायेगा। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रांतीय नेतृत्व के निर्देशानुसार विधायक एत्मादपुर धर्मपाल सिंह और विधायक फतेहपुर सीकरी चौ. बाबूलाल को जिला अध्यक्ष मुकेश शर्मा जिला मंत्री, प्रांतीय संगठन मंत्री एवं सदस्य फार्मेसी काउंसिल उ.प्र. रवीन्द्र सिंह राना, मंडल अध्यक्ष रा.क.सं.प. राजीव उपाध्याय, जिला संयोजक एवं प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाष बघेल, रामनरेश परमार, मुनेंद्र चाहर और कोषाध्यक्ष प्रवीण मिश्रा द्वारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम ज्ञापन प्रेषित किया गया। ज्ञापन सौंपने के बाद पत्रकार वार्ता में डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन उ.प्र. के प्रान्तीय संगठन मंत्री डा. रवीन्द्र सिंह राना ने बताया कि डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उ.प्र. के अधीन फार्मासिस्ट संवर्ग में उच्च पदों के वेतनमान, पद योग्यताएं और कार्यदायित्व सहित अन्य 24 सूत्रीय मांगों के संबंध में आदरणीय विधायकों को डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन, जनपद आगरा के पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित 24 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया गया।

(पार्श्वनाथ जन्मकल्याणक विशेष 25 दिसम्बर 2024) भगवान पार्श्वनाथ करुणावतार तो थे ही वे कर्मावतार भी थे

-संदीप सृजन

सनातन धर्म की पावन गंगोत्री से निकले विभिन्न धर्मों में जैन धर्म भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम धर्म है। चौबीस तीर्थंकरों की समृद्ध जनकल्याण की परम्परा, जो वर्तमान अवसर्पिणी काल में ऋषभदेव से लेकर महावीर तक पहुंची, उसमें हर तीर्थंकर ने अपने समय में जिन धर्म की परम्परा को और आत्मकल्याण के मार्ग को समृद्ध किया है तथा संसार को मुक्ति का मार्ग दिखाया है।

काल के प्रवाह में ऐसा होता आया है कि एक महापुरुष के निर्वाण के बाद उसका प्रभाव तब तक ही विशेष रूप से जन सामान्य में रहता है जब तक की उसके समान कोई अन्य महापुरुष धरती पर अवतरित न हो। लेकिन कुछ महापुरुष इसका अपवाद होते है। जैन धर्म के चौबीस तीर्थंकरों में तेवीसवें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के बाद भगवान महावीर हुए लेकिन भगवान पार्श्वनाथ के प्रभाव में कोई कमी आज तक नहीं आई है। जैन मान्यताओं के अनुसार वर्तमान में भगवान महावीर का शासन चल रहा है लेकिन सर्वाधिक जैन प्रतिमाएँ आज भी केवल भगवान पार्श्वनाथ की ही है। जैन मंत्र साधनाओं में भी सर्वाधिक महत्व पार्श्वनाथ के नाम को ही दिया जाता है।

भगवान पार्श्वनाथ का जन्म भगवान महावीर के जन्म से 350 वर्ष पहले हुआ। सौ वर्ष की आयु उनकी रही तदानुसार लगभग तीन हजार वर्ष पहले वाराणसी के महाराजा अश्वसेन के यहॉ माता वामा देवी की कुक्षी से पोष कृष्ण दशमी को हुआ। राजसी वैभव के बावजूद आत्मा में असीम करुणा का भाव जो सांसारिक जीवन में उनको लोकप्रिय बना देता है। वे उस दौर के तमाम आडम्बरों के बीच एक कमल पुष्प थे। धर्म और समाज में फैली हिंसा और कुरीतियों के बीच एक धर्म पुरोधा थे। जो मनुष्य समाज में मनुष्यता के गुण करुणा, दया, अहिंसा के जीवन की प्रतिस्थापना करने को आए थे।

जैन धर्म ग्रंथो में एक प्रसंग आता है- जब भगवान पार्श्वनाथ मात्र उम्र सोलह वर्ष थे तब वाराणसी नगरी में एक तापस आया जो नगर के मध्य अग्नी तप कर रहा था। और सारा नगर उस तापस के इस हठ योग से प्रभावित हो कर उसके दर्शन के लिए जा रहा था। ऐसे में लोक व्यवहार अनुसार पार्श्वकुमार भी वहॉ पहुंचे। तभी उन्होने अपने ज्ञान से देखा की तापस ने जो लकड़ी अपने सामने जला रखी है उसमें नाग नागिन का जोड़ा है, और वो जल रहा है। पार्श्वकुमार ने तापस से कहा कि- योगी आपके इस हठ योग में जीवों की हिंसा हो रही है। इस पर तापस क्रोधित हो गया और अशिष्ट भाषा का प्रयोग पार्श्वकुमार के प्रति किया। तभी पार्श्वकुमार ने अपने कर्मचारी को आदेश देते हुए काष्ठ के उस टुकड़े को आग से निकालने कर उसे चीरने को कहा, जैसे ही कर्मचारी ने लकड़ी को चीरा उसमें से जलता हुआ नाग नागिन का जोड़ा निकला जो

मरणासन स्थिती में पहुँच चुका था । पार्श्वकुमार ने जलते नाग नागिन के प्रति अपनी करुणा बरसाते हुए उनको नमस्कार महामंत्र सुनाया और बोध दिया कि वैर भाव को त्याग करे और समाधी मरण का वरण करे। पार्श्वकुमार की वाणी उस समय उस सर्प युगल के लिए किसी अमृत से कम नहीं थी। क्योंकि कहा जाता है 'अंत मति सो गति'। पार्श्वकुमार के वचनों से उनके मन से वैर भाव खत्म हुआ और वे समाधी मरण को प्राप्त कर देव लोक में धरणेन्द्र और पद्मावती नाम से इन्द्र और इन्द्राणी बने। जो की भगवान पार्श्वनाथ के जीवन काल में हर समय उनके साथ रहे और माना जाता है कि आज भी भगवान पार्श्वनाथ का स्मरण करने वाले के साथ रहते है।

भगवान पार्श्वनाथ करुणावतार तो थे ही वे कर्मावतार भी थे उन्होने अपने सत्तर साल के दीक्षा पर्याय में कभी किसी से सहायता की याचना नहीं की अपने तपोबल के माध्यम से केवल ज्ञान को प्राप्त किया। और मोक्ष को गये। भगवान पार्श्वनाथ कर्मकांड और आडम्बर को धर्म नहीं मानते थे वे जीवंत धर्म को ही धर्म मानने और उसकी प्रतिस्थापना करने के लिए धरा पर आए थे। उन्होंने करुणा, दया, परोपकार और जगत कल्याण के कार्यों को धर्म बताया और उसी तरफ जगत के जीवों के ले जाने के लिए उपदेश दिया। भगवान पार्श्वनाथ का जन्मकल्याणक मनाते हुए हमें भी उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए।

संपादक-शाश्वत सृजन

काशी में वरिष्ठ संत पूज्य अभिषेक ब्रह्मचारी जी और रोहित कुमार सिंह मुंबई में कोटि कुमकुमार्चन का भव्य आयोजन सफलता पूर्वक करवाने के बाद भाग्यनगर की धरती पर पधारे

परिवहन विशेष न्यूज

काशी में स्वामी करपात्री जी धाम और देश के वरिष्ठ संत पूज्य अभिषेक ब्रह्मचारी जी और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह मुंबई में 3 दिवसीय कोटि कुमकुमार्चन का भव्य आयोजन सफलता पूर्वक करवाने के बाद आज भाग्यनगर की धरती पर पधारे।

प्रेस विज्ञप्ति में श्री दक्षिणेश्वर केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन ठाकुर जयपाल सिंह नयाल सनातनी ने बताया कि कल शाम 3.30 बजे स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी और श्री रोहित कुमार सिंह जी लोअर टैंकबंड स्थित भाग्यनगर गौशाला में भव्य तुलसी पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे।

देश के वरिष्ठ संतों, विद्वानों और शंकराचार्यों के दिशा निर्देश पर भाग्यनगर में भी कल 25 दिसम्बर को तुलसी पूजन दिवस पर 701 तुलसी वृक्ष और 501 तुलसी महिमा पुस्तकों का वितरण श्री दक्षिणेश्वर केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट, सर्वदलीय गौरक्षा मंच, देवभूमि उत्तराखंड सेवा संस्थान तथा श्री योग वेदांत सेवा समिति हैदराबाद के संयुक्त तत्वाधान में किया जाएगा।

बच्चों के समग्र विकास में योगदान दें- स्वामी रामदयाल महाराज

डीपीएस भीलवाड़ा का वार्षिकोत्सव "स्मृतम 2024" उत्साहपूर्वक संपन्न

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा। वार्षिक उत्सव "स्मृतम 2024" का आयोजन अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ किया गया। इस वर्ष का मुख्य विषय "परिवार और रिश्तों का महत्व" था, जिसे छात्रों ने अपनी रचनात्मक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में लगभग 1500 छात्रों, अभिभावकों और अतिथियों ने भाग लिया। कार्यक्रम पालडी स्थित डीपीएस में किया गया

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना से हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में जगतगुरु स्वामी श्री रामदयाल महाराज (पीठाधीश्वर, रामस्नेही सम्प्रदाय, शाहपुरा) उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों में मांडल विधायक उदयलाल भड़ाना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस जैन, उपनिदेशक रोजगार (उदयपुर डिवीज़न) मुकेश गुर्जर, और स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य सत्यनारायण डाड व सुरेश तोषनीवाल शामिल थे। सभी ने छात्रों के प्रदर्शन की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने जानकारी देते हुए बताया कि छात्रों ने नृत्य, नाटक और संगीत के माध्यम से अपने कौशल का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षणों में "माता-पिता का महत्व," "परिवार में सामंजस्य," और "संस्कृति व नैतिक मूल्यों की ओर वापसी" पर आधारित प्रस्तुतियां थीं। इन भावनात्मक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को गहराई से प्रभावित किया। प्रधानाचार्य सुप्रिया जैन ने अपने संबोधन में कहा, "स्मृतम 2024 का उद्देश्य छात्रों को पारिवारिक मूल्यों और रिश्तों की अहमियत समझाना था। हमें गर्व है कि हमारे छात्रों ने इसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ प्रस्तुत किया।"

कार्यक्रम का समापन स्कूल गान के साथ हुआ। निदेशक रीना डाड और विनीता तोषनीवाल ने छात्रों की प्रतिभा की सराहना करते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। साथ ही, सलोनी डाड ने स्कूल की भविष्य की योजनाओं से अभिभावकों को अवगत कराया। मुख्य अतिथि स्वामी रामदयाल महाराज ने अपने प्रेरक वचनों से अभिभावकों और शिक्षकों को बच्चों के समग्र विकास में योगदान देने का संदेश दिया

20 मामले के आरोपी पी.एल.एफ.आई. उग्रवादी कैला यादव लातेहार से गिरफ्तार

कार्तिक परिच्छा, स्टेट हेड झारखंड

रांची, लातेहार पुलिस ने मंगलवार को कुख्यात उग्रवादी कैला यादव उर्फ संदीप को दबोच लिया है । लातेहार मानिका थाना के डेकी गांव के पास उसकी गिरफ्तारी के समय सात कारतूस समेत एक देशी पिस्तौल भी बरामद हुई हैं ।

मिली जानकारी के अनुसार उग्रवादी कैला यादव उर्फ संदीप के खिलाफ विभिन्न थानों में बीस मामले दर्ज हैं। उसे लातेहर पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने कैला को मंगलवार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादी कैला यादव उर्फ संदीप पिता भागीरथ यादव पांकी ,पलामू का रहने वाला बताया जाता है। पुलिस ने उसके पास से एक देसी कट्टा व सात जिंदा गोली बरामद किए हैं। इसकी जानकारी एसपी कुमार गौरव ने दी ।

एस पी ने कहा कि गुप्त सूचना के अनुसार पीएलएफआई के उग्रवादी कैला यादव किसी घटना को अंजाम देने के लिए डोंकी ग्राम के पास आया हुआ है। इसके बाद बरवाडीह एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा डोंकी गांव के आसपास रेकी कर छापेमारी की गई गिरफ्तार उग्रवादी पिछले कई वर्षों से लातेहार, पलामू, चतरा जिले में आगजनी, फायरिंग, लेवी वसूलने का कार्य कर रहा था। वह लंबे समय से फरार चल रहा था। कैला के ऊपर लातेहार,पलामू, चतरा जिले के विभिन्न थानों में हत्या , आगजनी, लेवी वसूली के 20 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095 . newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी .आर .बी . एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023